नई दिल्ली
रविवार
29 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 86
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य...पेज-05

DELHIN/2014/58158

कार्यकर्ता 'जन-मन का मैनिफेस्टो 2027' घर-घर...पेज-08

एक नजर

लोस में महिला आरक्षण और परिसीमन संबंधी विधेयक 30 नवंबर को पेश के लिए सूचीबद्ध

नई दिल्ली,हि.स.। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े हुए तीन महत्वपूर्ण विधेयक संसद के निचले सदन में सोमवार, 30 नवंबर को विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा कार्यवाही की शनिवार को जारी सूची के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को वापस लेने का प्रस्ताव पेश रखेंगे और फिर इसकी जगह पर नये विधेयक पेश करेंगे। वहीं, संविधान संशोधन से जुड़े दोनों विधेयक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे।

संसद के इस विशेष सत्र की बैठकें सोमवार 30 नवंबर से 03 दिसंबर तक निर्धारित हैं, जिसमें राज्यसभा की बैठक 02 दिसंबर से शुरू होगी। संसद की इस विशेष बैठक के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से सदनों की सदस्य संख्या में 50 फीसदी तक वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने का प्रावधान है। प्रस्ताव के अनुसार, नए परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन को वर्ष 2051 तक यथावत रखा जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करना है। इस उद्देश्य से संसद के विशेष सत्र में तीन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। लोकसभा में पेश होने वाले महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े इस संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत परिसीमन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। वहीं, संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का प्रावधान होगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए एक अलग विधेयक भी पेश किया जाएगा।

भारत-डेनमार्क ने द्विपक्षीय व्यापार व आर्थिक सहयोग और गहरा करने पर प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली। भारत और डेनमार्क ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को यह जानकारी दी। गोयल ने एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा कि डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि लार्स लोक्के रासमुसेन के साथ व्यापारिक संबंधों के विस्तार और सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर चर्चा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि हमने भारत-डेनमार्क साझेदारी को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, व्यावसायिक संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव बढ़ रहा है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकियों, समुद्री सहयोग और निवेश के क्षेत्रों में। इससे पहले इस महीने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026' के दौरान डेनमार्क के व्यापार और प्रतिस्पर्धा मंत्री मार्टिन लिडेगार्ड के साथ बातचीत की थी।

परिसीमन को हथियार बनाकर चुनाव क्षेत्रों का नक्शा बदलना चाहती है भाजपाः राहुल

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) परिसीमन को हथियार बनाकर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर निर्वाचन क्षेत्रों को अपने राजनीतिक हितों के अनुसार बदलते हुए विपक्षी दलों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करना चाहती है। श्री गांधी ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पहले से ही चुनावों में वोट चोरी कर रही है और अब उसने इसके लिए नया रास्ता निकालने की योजना बनायी है। लोकसभा की सीटें 850 करना लोकतंत्र को खत्म करने की भाजपा की योजना का प्रतीक है और इससे उसे देश के निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा अपनी सुविधा के अनुसार फिर से तैयार करने की व्यापक छूट मिल जायेगी। उन्होंने कहा, 'भाजपा अभी भी चुनावों में धांधली कर सकती है, लेकिन अब देश जानता है कि चुनावों में धांधली हो रही है। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार देश के 80 प्रतिशत लोग और लगभग 100 प्रतिशत जेनरेशन जेड का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव चोरी करते हैं और अब उन्होंने बच निकलने का नया रास्ता तलाश किया है।

श्री गांधी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान कर चुके 14 करोड़ मतदाताओं को अब अयोग्य बताते हुए मतदाता सूची से हटा दिया है। उन्होंने सवाल किया कि यदि निर्वाचन आयोग के अनुसार ये मतदाता अस्तित्व में ही नहीं थे अथवा मतदान के पात्र नहीं थे तो 2024 का लोकसभा चुनाव वैध कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इस सवाल का जवाब मांगा है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। श्री गांधी ने परिसीमन की प्रस्तावित व्यवस्था पर



सवाल उठाते हुए कहा कि अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं और भाजपा इन्हें बढ़ाकर 850 करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 543 सीटों के भीतर भी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा सकती है लेकिन 850 सीटें करने से भाजपा को कहीं अधिक बड़ा अवसर मिल जायेगा। इससे वह अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को तोड़ने, जोड़ने, मतदाताओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने और विपक्षी नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों की संरचना बदलने में सक्षम होगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक निर्वाचन क्षेत्र में 26 लाख और दूसरे में 19 लाख मतदाता हैं। उन्होंने असम के निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ क्षेत्रों के हिस्से भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं हैं। उनके अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों की ऐसी संरचना भाजपा के राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है और इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में भी किया जा सकता है। श्री गांधी ने कहा कि परिसीमन का सवाल केवल लोकसभा में राज्यों की सीटों के हिस्से को स्थिर रखने का नहीं है बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। उनका कहना था कि भाजपा 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि इसके लिए 2027 की नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नयी जनगणना से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी में वृद्धि सहित कई ऐसे तथ्य सामने आयेंगे, जिन्हें भाजपा सामने नहीं आने देना चाहती। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि परिसीमन नवीनतम जनगणना के आधार पर हो, राज्यों के लोकसभा में मौजूदा हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया जाए और महिला आरक्षण को 850 सीटों से जोड़ने के बजाय मौजूदा 543 सीटों पर लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग के गठन और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था भाजपा को निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा नये सिरे से तैयार करने की खुली छूट देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक दशक से अधिक समय से देश को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि वह वैध तरीके से चुनाव जीत रही है, जबकि कांग्रेस के अनुसार ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर पर्याप्त जानकारी जुटायी है और वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका से जुड़े तथ्यों को भी सामने लायेगी। श्री गांधी ने कहा, 'हमने मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार को घेर लिया है। ज्ञानेश कुमार के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी है और वह बचकर नहीं निकल पायेंगे। भाजपा देश को तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।' कांग्रेस नेता ने 'जेन जे' को संबोधित करते हुए कहा 'मोदी सरकार देश के युवा के भविष्य को बर्बाद करना चाहती है, देश के युवाओं की रोजगार को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं और आप जेन जे की ऊर्जा का इसके लिए पूरा इस्तेमाल किया जायेगा।'

उत्तराखंड में खाई में गिरी कार, आठ लोगों की मौत, चार घायल

पौड़ी गढ़वाल,एजेंसी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखणीखाल क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कलवाड़ी गांव के समीप यात्रियों से भरी इको कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। दुर्घटना के समय वाहन में चालक समेत कुल 12 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई में फंसे चारों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं, आठों मृतकों के शव भी खाई से निकाल लिए गए।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने बताया कि वाहन रिखणीखाल से भंगलवाड़ की ओर जा रहा था। इस दौरान कलवाड़ी के पास यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक 4 घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 8 लोगों की इस सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। घायल सभी व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र रिखणीखाल पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में कान्ति देवी पत्नी दिनेश चन्द्र निवासी भंगलवाड़ उम्र 45 वर्ष, रेखा देवी पत्नी प्रेम सिंह निवासी भंगलवाड़ उम्र 42 वर्ष, अनिल देवराड़ा पुत्र जयानन्द निवासी भंगलवाड़ उम्र 48 वर्ष (चालक), सुमित्रा देवी पत्नी रमेश सिह निवासी भंगलवाड़ उम्र 50 वर्ष, सुनीता देवी पत्नी मदन सिह निवासी भंगलवाड़ उम्र 45 वर्ष, धनेश्वरी देवी पत्नी किशन चन्द्र निवासी भंगलवाड़ उम्र 46 वर्ष, सरोजनी देवी पत्नी मोहन सिंह निवासी भंगलवाड़ उम्र 38 वर्ष, रजनी देवी निवासी भंगलवाड़ उम्र 25 वर्ष की मौत हो गई। घायलों में शशी देवी पत्नी गजेन्द्र सिंह निवासी भंगलवाड़ उम्र 35 वर्ष, शकुन्तला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी भंगलवाड़ उम्र 45 वर्ष, जगदीश सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी भंगलवाड़, सत्यवती देवी पत्नी जगदीश निवासी भंगलवाड़ उम्र 36 वर्ष शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस हृदयविदारक दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।

महिला आरक्षण का विरोध छोड़ कांग्रेस परिसीमन विधेयक का समर्थन करे: रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन विधेयक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से राजनीति छोड़ विधेयक का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं किया। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी दलों से विधेयक पारित कराने में सहयोग मांग रही है।



रिजिजू ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राज्यों के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ सांसदों और विधायकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि महिला सशक्तीकरण और जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के इस प्रयास पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। उन्होंने कांग्रेस से अपनी पुरानी सोच छोड़कर संसद में विधेयक का समर्थन करने की अपील की। रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं, एससी-एसटी समुदाय और सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखता है। इसका विरोध करने वालों को देश की महिलाएं और जनता माफ नहीं करेगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार पूरी तरह आश्वस्त है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चिंताएं और पक्ष स्पष्ट कर दिए हैं तथा उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों का समाधान किया गया है।

अन्नपूर्णा देवी और जयंत चौधरी ने हरिद्वार में 'नव्या 2.0' का शुभारंभ किया

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत संस्थान से 'नव्या 2.0' की शुरुआत की। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि 'नव्या 2.0' के तहत 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से आकांक्षी और दुर्गम क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पात्रता आयु सीमा को 16-18 वर्ष से बढ़ाकर 16-25 वर्ष कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें उद्योग की जरूरतों के अनुरूप, उभरते हुए और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार, अप्रेंटिसशिप और उद्यमिता के अवसर खुलेंगे। जिला स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए एक समान 'मानक संचालन प्रक्रिया' का पालन किया जाएगा।

महिला आरक्षण के रास्ते की हर बाधा दूर करेंगे, हमारा हौसला बुलंद और इरादा अडिगः मोदी

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण को संसद और विधानसभाओं में लागू करने के प्रति सरकार का दृढ़ संकल्प दोहराते हुए शनिवार को कहा कि नारी शक्ति को उनका अधिकार और उचित भागीदारी दिलाने के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां देश की महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएंगी, अब केवल समय का इंतजार है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो संदेश में कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दिलाने की लड़ाई कई दशकों से चल रही है और वह स्वयं भी वर्षों से इसके लिए प्रयास करने वालों में शामिल रहे हैं। देश की अनेक महिलाएं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर और पत्र लिखकर महिला आरक्षण का मुद्दा उठाती रही हैं।

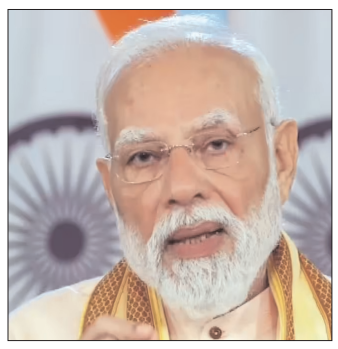

उन्होंने कहा, 'मैं जानता हूं कि देश की 100 प्रतिशत नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं कि हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटाकर रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अडिग है। मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएंगी। उन्होंने कहा कि अब केवल वक्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का विषय लंबे समय से चर्चा और प्रयासों का हिस्सा रहा है। इस दिशा में महिलाओं ने लगातार अपनी आवाज उठाई है और उनसे मिलकर तथा पत्रों के माध्यम से अपनी अपेक्षाएं रखी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि महिला आरक्षण को लेकर देश की महिलाओं का समर्थन सरकार के साथ है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में नए विधायी प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करने के लिए परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है।

बिना होमवर्क किए लगाते हैं आरोप राहुल गांधी, उनकी राजनीति में दिख रही हताशा: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी है कि वे बिना पूरी जानकारी के सरकार पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए।

इतना ही नहीं, उन्हें सलाह देने वाले लोगों को भी अपना होमवर्क ठीक से करना चाहिए। भाजपा मुख्यालय में शनिवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के मुद्दे पर



राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी इसे देश के राजनीतिक भूगोल को तोड़ने और तानाशाही लाने की कोशिश बता रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी तीन बार परिसीमन हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के शासन में परिसीमन हुआ, तब क्या देश में तानाशाही आ गई थी? उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि देश में तानाशाही की स्थिति तब बनी थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपातकाल लगा दिया था। रविशंकर प्रसाद ने सांसदों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर ब्रिटेन का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की आबादी करीब 5.88 करोड़ है, जबकि वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सांसद हैं। वहीं भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है। ऐसे में भारत में सांसदों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा करना गलत कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बेवजह भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों को समझना चाहिए।

अंडमान-निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली का मौसम रहेगा साफ

नई दिल्ली,एजेंसी। देश के दक्षिणी और द्वीपीय हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है जबकि देश के अन्य हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 30 नवंबर और एक दिसंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में अगले चार दिनों में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी और सुबह के समय कोहरे का असर बढ़ेगा। यहां 29 एवं 30 नवंबर को मौसम साफ रहेगा जबकि अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 25- 27 डिग्री सेल्सियस और 09-11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। एक दिसंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे जबकि सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा। आईएमडी के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में 28 नवंबर को तमिलनाडु,



पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा (अधिकतम 50 किमी प्रति घंटा) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, केरल, माहे और तमिलनाडु में कहीं-कहीं बारिश जारी रह सकती है। लक्षद्वीप में 28-29 नवंबर को व्यापक बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि 30 नवंबर और 2 से 4 दिसंबर के बीच भी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक (2-3 दिसंबर) में भी बारिश के आसार हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 29 नवंबर के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके असर से 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच यहां व्यापक बारिश होगी। खासतौर पर 30 नवंबर और एक दिसंबर को 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। 29 नवंबर और दो दिसंबर को भी 30-50 किमी प्रति घंटा की हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 3-4 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। वहीं, चार दिसंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश के साथ आंधी-तूफान और 30-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल, निचले क्षोभमंडल में गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से दक्षिणी गुजरात तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है।

एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग को मिला रोटरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता, एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास में होगी सहायक

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव एवं बर्न्स सर्जरी विभाग को रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 के साथ साझेदारी में आधिकारिक रूप से 'रोटरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में मान्यता दी गई है। इस साझेदारी के तहत गंभीर रूप से झुलसे लोगों, एसिड अटैक पीड़ितों, लिम्फेडेमा और डायबिटिक फुट से पीड़ित मरीजों को जटिल पुनर्निर्माण सर्जरी की सुविधा देने के साथ उनके समग्र पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएगा। इस मान्यता को विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंघल, एडिशनल प्रोफेसर डॉ. शशांक चौहान और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नंदिनी सिंह तंवर ने प्राप्त किया।



इस संबंध में शनिवार को एम्स में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटरी इंटरनेशनल की पूर्व अध्यक्ष और द रोटरी फाउंडेशन की चेयर जेनिफर जोन्स सहित रोटरी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।' लौटाए मुस्कान, संवारे जीवन' की थीम पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक मरीज को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। इसके तहत गंभीर रूप से झुलसे लोगों, एसिड अटैक पीड़ितों, लिम्फेडेमा और डायबिटिक फुट से पीड़ित मरीजों को जटिल पुनर्निर्माण सर्जरी की सुविधा देने के साथ उनके समग्र पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएगा। रोटरी के इतिहास में पहली बार भारत के किसी प्रमुख चिकित्सा संस्थान को यह दर्जा प्रदान किया गया है। डॉ. मनीष सिंघल ने पत्रकारों को बताया कि इस साझेदारी के तहत मरीजों को सर्जरी के अलावा मनोवैज्ञानिक परामर्श, शारीरिक पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल होने में मदद दी जाएगी। विशेष रूप से एसिड अटैक पीड़ितों और बर्न सर्वाइवर्स को स्कूल, कामकाज और सामान्य सामाजिक जीवन में लौटने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने बताया कि जलने की घटना किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। किसी हादसे में झुलसने वाले मरीजों को लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है। गंभीर रूप से जलने पर त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे मरीजों को कई बार एक से ज्यादा सर्जरी करानी पड़ती है। इलाज का मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना ही नहीं बल्कि शरीर के जले हुए हिस्सों को पहले जैसा बनाने और उनकी काम करने की क्षमता को बेहतर करना भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एम्स के बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक को अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेंटर के तहत डॉक्टरों के प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, शोध और भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच ज्ञान साझा करने पर भी जोर दिया जाएगा। विभाग की जरूरतों और आपसी सहमति के आधार पर आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य सुविधाओं के लिए भी संसाधन जुटाए जाएंगे। इस पहल में एम्स अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा, जबकि रोटरी अपने क्लबों, सदस्यों, दानदाताओं और रोटरी फाउंडेशन के पात्र कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधन जुटाएगा। रोटरी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी पहल के लिए एम्स या सरकार से किसी तरह का वित्तीय योगदान नहीं लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एम्स और रोटरी के बीच यह सहयोग पिछले कई वर्षों से चल रहे संयुक्त प्रयासों का विस्तार है। इसके तहत वर्ष 2022 में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक स्थापित किया गया था। अगस्त 2025 में एम्स में रोटाप्लास्ट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 80 से 100 मरीजों की सर्जरी की गई और 150 से अधिक लोगों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल के साथ ग्लोबल स्कॉलर्स प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके माध्यम से एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों और विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर मिलेगा।

सोनिया गांधी से जुड़ी मतदाता सूची संबंधी शिकायत तुगलक रोड थाने भेजी गई, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोपों वाली शिकायत को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया गया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को आईपी इस्टेट थाने से तुगलक रोड पुलिस थाने को भेज दिया गया है क्योंकि ये मामला उसी थाना क्षेत्र का है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस मामले को तुगलक रोड थाने भेजा गया है।

इसके पहले कोर्ट ने 18 नवंबर को दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया था। 18 नवंबर को शिकायतकर्ता और वकील विकास त्रिपाठी ने 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियां जमा की थीं। 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामला मजिस्ट्रेट को वापस भेजते हुए कहा था कि इस पर दोबारा विचार करें और तर्कसंगत आदेश पारित करें। विशाल गोड़ने ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश तर्कसंगत नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को वकील विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके पहले 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं। याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं। बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया। सोनिया गांधी भारत की नागरिक 1983 में बनीं। याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 में दिया था। याचिका में कहा गया था कि जब सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं तो 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। ऐसे में कोर्ट सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे।

नीट पेपर लीक मामले के आरोपित डॉ. मनोज शिरुरे की दूसरी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपित डॉ मनोज भगवानराव शिरुरे की दूसरी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। न्यायालय ने 27 नवंबर को जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया था। इसके पहले राऊज एवेन्यू ने 24 जुलाई को शिरुरे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जुलाई में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने शिरुरे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये अपराध राष्ट्र के खिलाफ है। सीबीआई ने कहा था कि इस अपराध ने देश की छवि को खराब किया है और लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पेपर लीक की वजह से परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। कई छात्रों को कठिनाई झेलनी पड़ी। इससे सरकार को भी करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। पेपर लीक की घटना के बाद कई छात्रों ने खुदकुशी तक कर ली। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में 12 मई को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 03 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।

सच्चे नेतृत्व की पहचान पुरस्कारों से नहीं, योगदान से होती है : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सच्चे नेतृत्व की पहचान हमें मिलने वाले पुरस्कारों से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन, संस्थाओं व समाज में हमारे सकारात्मक योगदान से होती है। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा आयोजित प्रथम यूथ बोर्ड मीटिंग (वाईबीएम) प्रतियोगिता 2026 के राष्ट्रीय चरण को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की छात्र टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता ने युवाओं को अपने नेतृत्व कौशल, कॉरपोरेट गवर्नेंस की समझ, रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए और सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।



प्रतिभागियों को बधाई देते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय चरण तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह उनकी मेहनत, टीम भावना, लगन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस दूरदर्शी पहल के लिए आईसीएसआई की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से युवा कॉरपोरेट बोर्ड की कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो नवाचार और रणनीतिक सोच के साथ ईमानदारी, जवाबदेही और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को भी अपनाएं। विधायी संस्थाओं और कॉरपोरेट बोर्डरूम की कार्यप्रणाली में समानता बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही स्थानों पर संवाद, अलग-अलग विचारों का सम्मान, पारदर्शिता और सामूहिक सोच के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व केवल अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की बात सुनने, सहमति बनाने और संस्था एवं समाज के व्यापक हित में निर्णय लेने की क्षमता है। यूथ बोर्ड मीटिंग प्रतियोगिता युवाओं में इन्हीं गुणों को विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अपने विद्यार्थी जीवन और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका को याद किया।

मानहानि मामला : प्रवेश वर्मा की याचिका पर सौरभ भारद्वाज को जवाब के लिए मिला समय

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सौरभ भारद्वाज को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने 6 नवंबर को सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अक्टूबर को वर्मा की शिकायत खारिज कर दी थी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया। प्रवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पोस्ट किया। याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया। याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपित हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि सौरभ भारद्वाज के ये पोस्ट समाज की नजरों में उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किए। इसी मामले में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी मानहानि का केस दायर किया था। उच्च न्यायालय में दाखिल दीवानी मानहानि याचिका में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला: अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों पर फैसला 12 दिसंबर तक टला

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अब 12 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। इसके पहले भी कोर्ट ने 3 नवंबर को फैसला टाल दिया था। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी। 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।



इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई। चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनीलांडरिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था। करीब पांच हजार पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है।

सरकार ने कच्चे जूट की जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय की

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की जमाखोरी रोकने और आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए नई स्टॉक सीमा तय कर दी है। ये आदेश जूट बेलरों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों और जूट मिलों पर लागू होगा। वस्त्र मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि जूट आयुक्त ने 27 नवंबर 2026 को कच्चे जूट की जमाखोरी को रोकने और कीमतों में उतार-चढ़ाव पर अंकुश लगाने के लिए गांठ बनाने वाली इकाइयों, भंडारकों, व्यापारियों और जूट मिलों के पास इसके भंडार की सीमा तय कर दी है। इसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक भंडार रखने वालों को अतिरिक्त स्टॉक को बेचकर 10 दिसंबर तक खरीदारों को उसकी वास्तविक आपूर्ति करनी होगी। जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण का आदेश, 2016 के तहत 27 नवंबर को जारी किया गया है। यह आदेश कच्चे जूट की कीमतों में अस्थिरता और सट्टेबाजी के कारण कीमतों में हो रही वृद्धि की चिंताओं के बीच आया है। जूट आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वे स्टॉकिस्ट/बेलर जो अधिसूचना की तिथि तक पंजीकृत नहीं हैं और जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है तथा पंजीकृत स्टॉकिस्ट/बेलर जो जूट स्मार्ट पोर्टल पर स्टॉक रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं, अधिकतम 5 क्विंटल। कच्चे जूट से जूट सामान बनाने वाली जूट मिलें/विनिर्माण इकाइयाँ: वर्तमान उत्पादन दर के अनुसार अधिकतम 90 दिनों की खपत। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने वाली संस्थाओं को अतिरिक्त मात्रा बेचनी होगी और 10 दिसंबर 2026 को या उससे पहले उसे प्रेषिती को भौतिक रूप से सौंपना होगा। तत्काल प्रभाव से, जब तक रखा गया स्टॉक निर्धारित सीमा के भीतर न आ जाए, नए स्टॉक की सभी खरीद रोक दी जानी चाहिए।

दिल्ली भाजपा कोर ग्रुप की घोषणा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 12 सदस्य, 3 विशेष आमंत्रित

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली प्रदेश इकाई के कोर ग्रुप की शनिवार को घोषणा कर दी। कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 12 नेताओं को सदस्य और 3 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा इस कोर ग्रुप के अध्यक्ष हैं। भाजपा के मुताबिक इस कोर ग्रुप को दिल्ली में पार्टी की रणनीति, संगठन विस्तार और सरकार एवं संगठन के बीच समन्वय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन, पंजाब के प्रदेश सह-प्रभारी वीरेंद्र सचदेवा, राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, विधायक सतीश उपाध्याय, अरविंदर सिंह लवली को सदस्य बनाया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश सह-प्रभारी जे. सेरिंग नामग्याल और प्रदेश सह-प्रभारी दर्शना जारदोष को शामिल किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह कोर ग्रुप दिल्ली में आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक फैसलों और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।

रेलवे बोर्ड ने दिल्ली सहित 37 मंडलों में नए डीआरएम नियुक्त किए, कई अधिकारियों के तबादले

नई दिल्ली,एजेंसी। रेलवे बोर्ड ने देश के विभिन्न रेलवे जोनों के 37 मंडलों में मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) की नियुक्ति और तबादले के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में दिल्ली मंडल भी शामिल है, जहां संजय सिंह को नया डीआरएम नियुक्त किया गया है। वह पुष्पेश आर. त्रिपाठी का स्थान लेंगे। रेलवे बोर्ड ने 27 नवंबर को जारी आदेशों में इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की बात कही है। आदेश के अनुसार, संजय सिंह मध्य रेलवे में एनएफ-एचएजी/भारतीय रेल विद्युत अभियंता सेवा (आईआरएसईई) के अधिकारी हैं। उन्हें उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल का डीआरएम बनाया गया है। पुष्पेश आर. त्रिपाठी के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने नियुक्तियों के प्रभावी होने की तारीख संबंधित अधिकारियों से बाद में बताने को कहा है। रेलवे बोर्ड के आदेशों के तहत सुबिन कुमार को पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू मंडल, नरेंद्र कुमार लोहिया को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल और दीपक नारायण काटे को मध्य रेलवे के मुंबई मंडल का डीआरएम नियुक्त किया गया है। अक्षय कुमार मरनरु को उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल तथा मनीषा चटर्जी को उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल की जिम्मेदारी दी गई है।



समीर शंकर को दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली मंडल, नितिन बंसल को उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल और अमित कुमार जैन को पूर्व तटीय रेलवे के संबलपुर मंडल का डीआरएम बनाया गया है। पृथुल कुमार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल तथा शिखा श्रीवास्तव को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मनोज कुमार गंगैया को पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल, वीणा कुमारी वर्मा को उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल और यशवंत कुमार चौधरी को पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल का डीआरएम नियुक्त किया गया है। अर्चना मित्तल को पूर्व रेलवे के मालदा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। अमित श्रीवास्तव को दक्षिण तटीय रेलवे के विशाखापत्तनम मंडल, सुधीर कुमार सरवरिया को पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल और गुनींदर सिंह नरंग को पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल का डीआरएम बनाया गया है। इंदरजीत दिहाना को मध्य रेलवे के नागपुर मंडल तथा नेकराज श्रीवास्तव को पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत कुमार को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग मंडल और अमनदीप कपूर को उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल का डीआरएम नियुक्त किया गया है। नेकराज वर्मा को दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल तथा नवीन कुमार अग्रवाल को दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप कुमार श्रीवास्तव को पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल, सत्येंद्र के. शुक्ला को दक्षिण तटीय रेलवे के चेन्नई मंडल और भारद्वाज चौधरी को मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल का डीआरएम बनाया गया है। पवन प्रिया राजू को पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगेंद्र बघेल को दक्षिण मध्य रेलवे के गुन्टकल मंडल का डीआरएम नियुक्त किया गया है। शरद शर्मा को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया मंडल का डीआरएम बनाया गया है। अमिता शुक्ला को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल, अभिजीत कुमार सिन्हा को दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूर मंडल और भास्कर चोरड़िया को पूर्व तटीय रेलवे के रायगढ़ा मंडल का डीआरएम नियुक्त किया गया है। राजेश तिवारी को पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल तथा देवेंद्र कुमार चौधरी को दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। मनीष चंद्र को दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल और हर्षा दास को मध्य रेलवे के पुणे मंडल का डीआरएम नियुक्त किया गया है।

विकासपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 1,800 लोगों ने उठाया लाभ

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विकासपुरी के शिव विहार पश्चिम स्थित विधायक कार्यालय में आज नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में लगभग 1,800 लोगों ने पंजीकरण कराया और नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की जांच, दांतों की जांच, ईसीजी तथा स्त्री रोग विशेषज्ञों और फिजिशियन सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श जैसी अनेक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इस पहल के तहत आंखों की जांच के बाद लगभग 500 लोगों को नि:शुल्क चश्मे वितरित किए गए। वहीं, करीब 600 लोगों के बीपी एवं शुगर की जांच की गई, 300 लोगों ने दंत चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया तथा लगभग 100 लोगों की ईसीजी जांच की गई। इसके अतिरिक्त अन्य चिकित्सकीय परामर्श एवं स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं भी पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई गईं। डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श बीमारियों की शुरुआती पहचान एवं उनकी रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक नजर

दो बाइक पर 164 चालान का 7.45 लाख जुर्माना, दोनों जब्त

गुरुग्राम। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस की अलग-अलग टीमों ने भारी संख्या में लंबित चालानों वाली दो मोटरसाइकिलों को इंपाउंड किया। पहली कार्रवाई में एचएचओ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन-1, निरीक्षक लोकेश और उनकी टीम ने एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रुकवाया। वाहन चालक से मोटरसाइकिल के जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच के दौरान मोटरसाइकिल पर कुल 31 चालान लंबित पाए गए, जिनकी जुर्माना राशि 4,84,000 रुपये थी। इनमें मुख्य रूप से बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा बिना बीमा के वाहन चलाने से संबंधित चालान शामिल थे। दूसरी कार्रवाई में जोनल ऑफिसर आर्टेमिस टी-पॉइंट पर एसआई राजपाल और उनकी टीम ने एक अन्य मोटरसाइकिल को जांच के लिए रुकवाया। वाहन चालक से आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में इस मोटरसाइकिल पर 133 चालान लंबित पाए गए, जिनकी कुल जुर्माना राशि 2,61,000 रुपये थी। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना बीमा के वाहन चलाने तथा रोड मार्किंग का उल्लंघन करने जैसे यातायात नियमों से संबंधित चालान शामिल थे। भारी संख्या में चालान लंबित पाए जाने पर दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करवाया गया। दोनों मोटरसाइकिलों पर 164 चालान लंबित थे, जिनकी जुर्माना राशि 7,45,000 रुपये है।

ऑनलाइन मुनाफे का लालच देकर की दो लाख 31 हजार की ठगी

फरीदाबाद। ऑनलाइन निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर एक व्यक्ति से दो लाख 31 हजार 860 रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने एक खाताधारक को जयपुर (राजस्थान) से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिग्विजय सिंह निवासी जयपुर के रूप में हुई है। आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम में से 80 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, बल्लभगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी थी कि 3 अक्टूबर 2026 को उसकी बातचीत sangam.com के माध्यम से एक युवती से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच टेलीग्राम पर बातचीत होने लगी। इस दौरान कथित युवती ने उसे ऑनलाइन निवेश के जरिए अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल दो लाख 31 हजार 860 रुपये उसके बताए खातों में भेज दिए। बाद में ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने ठगी की रकम प्राप्त करने वाले बैंक खाते के खाताधारक दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बीटेक पास है और जयपुर की एक निजी कंपनी में आईटी डेवलपर के रूप में कार्यरत है। उसके बैंक खाते में ठगी के 80 हजार रुपये आए थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

निजी कंपनी में लिफ्ट में दबकर हुई युवक की मौत

फरीदाबाद। फरीदाबाद स्थित एक निजी कंपनी में माल ढोने वाली लिफ्ट में दबने से 31 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा देखकर कंपनी के कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। किसी तरह उसे लिफ्ट से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस और मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी विपिन के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, विपिन की शादी महज पांच महीने पहले हुई थी। वह करीब दो महीने पहले ही रोजगार की तलाश में फरीदाबाद आया था। मृतक के जीजा ने आरोप लगाया कि काम के दबाव के चलते विपिन को माल ढोने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। काम जल्द पूरा करने की हड़बड़ी में यह हादसा हुआ। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजेश के मुताबिक, वह भी इस कंपनी में काम करता है। करीब दो महीने पहले ही उसका साला विपिन रोजगार की तलाश में फरीदाबाद आया था। यहां सेक्टर-58 स्थित एक निजी कंपनी में काम करने लगा था। शुक्रवार शाम काम के दौरान विपिन माल ढोने वाली लिफ्ट में दब गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। कंपनी की ओर से परिवार को इसकी जानकारी दी गई। परिवार जब मौके पर पहुंचा तो पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम हाउस भेज चुकी थी। राजेश का आरोप है कि कंपनी में कर्मचारियों पर काम का काफी दबाव रहता था। इसी दबाव के चलते कर्मचारियों को माल ढोने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। उनका कहना है कि काम जल्द पूरा करने की हड़बड़ी में विपिन को भी इस लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। राजेश ने बताया कि विपिन की शादी करीब पांच महीने पहले ही हुई थी। वह अपने परिवार का भविष्य संवारने और नई गृहस्थी की जिम्मेदारियां उठाने के लिए नौकरी कर रहा था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया।

अर्बन मोबिलिटी के सिद्धांतों के अनुरूप विकसित हों आधुनिक सड़कें : सैनी



गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सनाथ रोड की तर्ज पर अर्बन मोबिलिटी के सिद्धांतों के अनुरूप आधुनिक सड़कें विकसित की जाएं। इन सड़कों की डिजाइनिंग इस प्रकार हो कि वाहनों के सुगम आवागमन के साथ पैदल राहगीरों और साइकिल चालकों को भी पर्याप्त स्थान मिले। उन्होंने सभी सड़कों पर फुटपाथ की डिजाइन में एकरूपता रखने, पैदल यात्रियों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने तथा जल निकासी के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में राहगिरी फाउंडेशन और नगारो फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में मिले सुझावों पर दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के ढांचागत विकास, सौन्दर्यीकरण तथा शहरी मोबिलिटी और सड़क विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। बैठक में दोनों फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने आधुनिक सड़कें विकसित करने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित करने से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए अर्बन फॉरेस्ट की तर्ज पर नए स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों की पहचान की जाए, जहां अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाकर नए हरित क्षेत्र विकसित किए जा सकें। इसके साथ ही त्रिवेणी और मियावाकी पद्धति के अनुरूप पौधारोपण को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सड़क विकास योजनाओं के साथ पौधारोपण और हरित क्षेत्र विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि शहर में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सके। बैठक में स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित करने के विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुरुग्राम के सभी सेक्टरों में उपयुक्त स्थानों की पहचान कर निर्धारित स्ट्रीट वेंडिंग जोन विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी संचालकों को व्यवस्थित स्थान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि उनका रोजगार भी प्रभावित न हो और फुटपाथ, सड़क तथा ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण की स्थिति भी पैदा न हो। इसके अलावा उन्होंने शहर में चार स्थानों पर सब्जी मंडियों के लिए उपयुक्त जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए, ताकि बाजारों को व्यवस्थित किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से शहर में म्यूजियम के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि शहर में जहां भी सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, वहां संबंधित विभाग और नगर निगम निर्माण के समय ही यूटिलिटी पाइप और आवश्यक डक्ट डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इससे भविष्य में पेयजल, सीवर और अन्य उपयोगिताओं से संबंधित कार्यों के लिए बार-बार सड़कों की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी।

गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिक वापस भेजे गए

गुरुग्राम। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने जिले में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को नियमानुसार वापस भेजने की प्रक्रिया के तहत ट्रेन के माध्यम से रवाना कर दिया। सभी को पुलिस कर्मचारियों की कड़ी सुरक्षा और निगरानी में भेजा गया। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल कोच भी अटैच करवाया गया था।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गुरुग्राम पुलिस द्वारा जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, सत्यापन और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, गुरुग्राम पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तथा पीओ स्टाफ की अलग-अलग कार्यवाहियों के दौरान इन 27 बांग्लादेशी व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था।

ये लोग गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे थे। शुरुआती जांच में इनके पास भारत में रहने से संबंधित वैध वीजा, पासपोर्ट अथवा अन्य आवश्यक अनुमति नहीं पाई गई। पूछताछ में भी ये लोग भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और यहां रहने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को नियमानुसार डिटेंशन सेंटर, मानेसर भेजा गया था, जहां उनके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया अमल में लाई गई। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

गुरुग्राम में बढ़ती जरूरतों के अनुसार होगा सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार: नायब सिंह सैनी

गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गुरुग्राम में 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) के बेड़े में शामिल की गई ये बसें यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाएंगी। ये 100 बसें गुरुग्राम जिले के 20 विभिन्न रूटों पर संचालित होंगी, जिससे शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 17 करोड़ की लागत से विकसित सेक्टर-48 स्थित जीएमसीबीएल के नए ई-बस डिपो का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम के विकास और सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में आज एक नई शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ और सेक्टर-48 में आधुनिक ई-बस डिपो का लोकार्पण गुरुग्राम को स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल शहर की बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की यात्रा वर्ष 2018 में 25 बसों के साथ शुरू हुई थी। अब गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड के बेड़े में 150 सीएनजी बसें संचालित हैं। इनमें 100 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से कुल बसों की संख्या बढ़कर 250 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना देश के शहरों में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय प्रयास है। इस योजना के तहत देशभर में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुरुग्राम में 100 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ इसी व्यापक राष्ट्रीय संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्रीनायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख केंद्र है। यहां देश-विदेश की कंपनियां, उद्योग, आईटी और सेवा क्षेत्र के संस्थान स्थापित हैं। प्रतिदिन लाखों लोग रोजगार, शिक्षा, व्यापार और अन्य आवश्यकताओं के लिए शहर में आवागमन करते हैं।

जलभराव कम करने के लिए एफएमडीए अरावली में बनाएगा बांध

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

फरीदाबाद। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने और शहर के निचले इलाकों में बारिश के पानी से होने वाली परेशानी कम करने के लिए एफएमडीए अरावली के पानी को पहाड़ियों में ही रोकने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अरावली क्षेत्र में बांध बनाने की योजना बनाई गई है। परियोजना को अमलीजामा पहनाने से पहले इसकी तकनीकी रूपरेखा तैयार कराई जा रही है। बांध के संभावित स्थान और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का जायजा लेने के लिए चंडीगढ़ सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर जगमोहन नेगी अपनी टीम के साथ सर्वे कर चुके हैं। इस संबंध में एफएमडीए अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बांध का डिजाइन तैयार किया जाएगा।



हर साल मानसून के दौरान अरावली से निकलने वाला बरसाती पानी नालों और नहरों के जरिए यमुना में पहुंचता है। उस समय यमुना का जलस्तर पहले ही बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में पहाड़ियों से आने वाला अतिरिक्त पानी आसपास के गांवों के लिए मुसीबत बन जाता है। इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशने के लिए एफएमडीए पानी के बहाव को नियंत्रित करने की योजना पर काम कर रहा है। अरावली का पानी नियंत्रित होने से एनआईटी, बल्लभगढ़, सेक्टरों और कॉलोनियों में जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है। बारिश के समय शहर के कई इलाकों में सड़कों पर दो-तीन फीट तक पानी जमा हो जाता है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। एफएमडीए का मानना है कि बांध बनने के बाद पानी का अनियंत्रित बहाव कम होगा। साथ ही पहाड़ियों में जमा बारिश के पानी को भूजल रिचार्ज के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे भूजल स्तर सुधारने और पानी की कमी वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने में मदद मिल सकती है। एफएमडीए के अधीक्षण अभियंता (अतिरिक्त कार्यभार) संदीप दहिया ने बताया कि अरावली में बांध बनाने की योजना पर काम चल रहा है। चंडीगढ़ सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर जगमोहन नेगी इसका डिजाइन तैयार करेंगे। डिजाइन मिलने के बाद निर्माण का एस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा।

गुरुग्रामः परिसीमन व महिला आरक्षण के संशोधित प्रस्तावों को मंजूरी का किया स्वागत



गुरुग्राम,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 नवंबर को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में परिसीमन एवं महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित विधायी प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने का भाजपा गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी नारी शक्ति को नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक हिना शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े संशोधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना असंख्य माताओं और बेटियों की आकांक्षाओं को स्वर देने की पहल है। भाजपा महिला मोर्चा हरियाणा की प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मि अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अजय दुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बाद अब संसद में इन पर व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। विपक्ष से अपेक्षा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कराने में सहयोग करे। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉ. विशिका यादव जैन ने कहा कि महिलाएं केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति निर्माता, निर्णयकर्ता और राष्ट्र निर्माण की नेतृत्वकर्ता भी बनें। नारी शक्ति की सक्रिय सहभागिता विकसित भारत की मजबूत आधारशिला है। गुरुग्राम भाजपा जिला प्रवक्ता सुशीला कटारिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिसीमन के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना संतुलित संसदीय प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

सड़क हादसे में हुई कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत

फरीदाबाद। फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में एफसीआई के गोदाम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 31 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव दयालपुर निवासी रवि के रूप में हुई है। मृतक के चाचा वीरेंद्र ने बताया कि रवि पिछले सात साल से एफसीआई के गोदाम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहा था। शुक्रवार शाम को ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपनी वैगनआर कार से घर लौट रहा था। उसके साथ एक दोस्त भी मौजूद था। इसी दौरान मच्छगर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार रवि की जान चली गई। रवि परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके पिता खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि छोटा भाई एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। करीब छह साल पहले रवि की शादी हुई थी। उसका चार साल का एक बेटा भी है। परिवार को उम्मीद थी कि रवि नौकरी कर घर की जिम्मेदारियां संभालेगा, लेकिन सड़क हादसे ने परिवार का सहारा छीन लिया।

मन का शोर थामने का जरिया है आध्यात्मिकता: उपेंद्र राय

गुरुग्राम। सूचनाओं की तेज रफ्तार, बढ़ते शोर और बदलते दौर की चुनौतियों के बीच सुर्खियों से परे आंतरिक शोर से आंतरिक स्पष्टता की ओर विषय पर तीन दिवसीय मीडिया रिट्रीट का शुभारम्भ ब्रह्माकुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हुआ।

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भारत एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्थान में आने से मन का शोर समाप्त होता है और संगत का गहरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाहर की आग को तो आसानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन भीतर की आग को बुझाने के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत है। जिस प्रकार नदियों का शोर सागर में जाकर ही थमता है, ठीक उसी प्रकार मन का शोर भी ईश्वर से जुडने से ही थम सकता है। उपेंद्र राय ने कहा कि स्थूल नेत्रों से परे भी एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व है। ज्ञान भीतर से ही आलोकित होता है, जरूरत है उसे गहराई से महसूस करने की। उन्होंने कहा कि जीवन में कई मुश्किलें अधिक बोलने से पैदा होती हैं। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी ने कहा कि मीडिया को बाहर की दुनिया से कहीं अधिक अपने भीतर की दुनिया को महसूस करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सबसे मिलते रहते हैं, लेकिन स्वयं से नहीं मिलते, जबकि आध्यात्मिकता हमें स्वयं से मिलाती है।

विश्व के परिवर्तनशील चक्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया श्रेष्ठ पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रही है, जिसकी शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए और मीडिया को सबके लिए उदाहरण बनना होगा। राजयोगिनी शुक्ला दीदी ने कहा कि मीडिया समाज की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखता है, लेकिन मौजूदा दौर में मूल्यों की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी बदलाव के लिए अपने अंदर की आवाज सुनना जरूरी है और आज मीडिया जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उनका समाधान आध्यात्मिकता में ही समाहित है।

गुरुग्रामः साझेदारी में बेचते थे मूंगफली, पैसों का विवाद हत्याकांड तक पहुंचा

गुरुग्राम। पैसों के लेनदेन के विवाद में 25 वर्षीय युवक की चाकू से वार करके व गला घोंटकर हत्या करने तथा शव को जमीन में दबाने के मामले में पुलिस थाना सेक्टर-65, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने शनिवार को बताया कि इस मामले में अब तक सभी तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

11 नवंबर 2026 को पुलिस थाना सेक्टर-65 में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई नईम के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसका भाई नईम (उम्र करीब 25 वर्ष) गुरुग्राम में मूंगफली बेचने का काम करता था। आठ नवंबर 2026 की शाम वह बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर लेने दिल्ली जाने की बात कहकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में सेक्टर-50 में एक मोबाइल फोन मिलने की सूचना पर शिकायतकर्ता ने वहां जाकर फोन प्राप्त किया, जो उसके भाई का था। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सेक्टर-65 में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा इस मामले में आरोपी बबलू (उम्र 21 वर्ष), निवासी जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी बबलू और मृतक नईम पिछले चार-पांच वर्षों से गुरुग्राम में साझेदारी में मूंगफली बेचने का काम करते थे। दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आठ नवंबर 2026 को सेक्टर-63 कादरपुर टी-पॉइंट के पास बनी झुग्गियों में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोपी बबलू ने मृतक नईम पर चाकू से वार किया तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने अपने पहने हुए कपड़े जला दिए तथा मृतक के शव को पास स्थित पुराने पानी के टैंक में गड्ढा खोदकर दबा दिया और ऊपर से नमक डालकर मिट्टी से ढक दिया। सेक्टर-65 थाना प्रभारी निरीक्षक रामबीर सिंह के नेतृत्व में इस हत्याकांड में दो अन्य आरोपियों को शनिवार को गांव बेहटा गोसाई, जिला बदायूं (उत्तर

मेटा इंडिया कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने दिया धरना

गुरुग्राम। गुरुग्राम स्थित मेटा इंडिया मुख्यालय के बाहर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में शनिवार को युवा कांग्रेस ने हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक आवाजों को कथित रूप से दबाए जाने के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने युवा कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने, सरकार से सवाल पूछने और युवाओं के मुद्दों को देश के सामने रखने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। ऐसे में यदि किसी राजनीतिक विचारधारा, संगठन या विपक्ष की आवाज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दबाने का प्रयास किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।



उन्होंने कहा कि कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेटा प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन नियमों और आधारों पर ये कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई अकाउंट नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन नियमों का इस्तेमाल किसी की राजनीतिक आवाज दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। चिब ने आगे कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां लोकतंत्र में बड़ी भूमिका निभा रही हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता के सिद्धांतों पर काम करें। किसी भी सरकार, राजनीतिक दल या विचारधारा के दबाव में आकर कार्रवाई करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और युवा कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट बंद या प्रतिबंधित किए गए हैं। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए विरोध दर्ज करवाया।

प्रतिबंध से आगे बढ़े कार्रवाई, आतंकियों की संपत्ति बने राष्ट्र की संपदा

डॉ. मयंक चतुर्वेदी



केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के खिलाफ जो कदम उठाया है, वह आतंकवाद से लड़ने के उस सिद्धांत की ओर इशारा है जिसे लंबे समय से लागू किए जाने की जरूरत थी। 13 नवंबर 2026 को यूएपीए की धारा 3(1) और 3(3) के तहत आईआरएफ पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद 26 नवंबर को गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर धारा 42 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धारा 7 और 8 के अधिकार सौंपे हैं। वस्तुत: अब राज्य सरकारें इस प्रतिबंधित संगठन के फंड, बैंक खातों, वित्तीय संपत्तियों के लेन-देन पर रोक लगा सकती हैं, संदिग्ध लेन-देन की जांच कर सकती हैं और उन परिसरों को अधिसूचित कर सकती हैं जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों के लिए हो रहा था। यह फैसला सही दिशा में है, किंतु इसे अपवाद नहीं, नियम बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आतंकवाद सिर्फ हथियार और नारेबाजी से नहीं टिकता, उसकी असली ताकत धन में होती है इसलिए जब तक आतंकवादी संगठनों और उनके सदस्यों के बैंक खाते खुले रहेंगे, जमीन-जायदाद उनके नाम या फ्रंटों के नाम पर रहेगी, तब तक वे नए रूप में उठ खड़े होंगे। ऐसे में असली कड़ी कार्रवाई यही है कि दोषसिद्ध आतंकियों की पूरी संपत्ति जब्त की जाए, बेची जाए और उससे प्राप्त राशि सीधे सरकारी खजाने में जमा की जाए। इस तरह से जिस भी व्यक्ति का आतंक का अपराध न्यायालय में सिद्ध हो चुका हो, उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी जाए। जाकिर नाइक और आईआरएफ का मामला इसका ताजा उदाहरण है। संगठन पर 2016 में पहली बार प्रतिबंध लगा। नाइक उस समय से मलेशिया में रह रहा है। उनका पासपोर्ट रद्द है, प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी हैं, फिर भी संगठन लंबे समय तक सक्रिय रहा। प्रतिबंध बढ़ाने और राज्यों को अधिकार देने का ताजा फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर फंड और परिसरों पर कार्रवाई हो सकेगी। सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) का इतिहास बताता है कि अकेले प्रतिबंध से काम नहीं चलता। सिमी पर 2001 से प्रतिबंध है और इसे बार-बार बढ़ाया गया है। क्योंकि सिमी के सदस्य इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस और अन्य संगठनों से जुड़े रहे। कई सदस्यों पर आतंक के मामले दर्ज हुए, आरोप सिद्ध हुए और सजा हुई। उनके मुख्यालय और परिसर सील किए गए। फिर भी सिमी के पुराने कार्यकर्ता नए संगठनों में सक्रिय होते रहे। यदि दोषसिद्धि के तुरंत बाद उनकी व्यक्तिगत और संगठनात्मक संपत्तियों को जब्त कर बेचा गया होता और रकम खजाने में जमा की गई होती तो स्वभाविक है, पुनर्गठन की प्रक्रिया कमजोर पड़ती।

अत: यहां सिमी का उदाहरण स्पष्ट करता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक कार्रवाई को स्थायी और स्वचालित बनाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों पर 2022 में प्रतिबंध लगा। एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि संगठन ने बड़े पैमाने पर फंड जुटाए, शारीरिक प्रशिक्षण शिविर चलाए और आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया। ईडी ने पीएफआई से जुड़े ट्रस्टों और संपत्तियों को अटैच किया। एक चरण में 67 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच हुईं और कुल अटैचमेंट 129 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया।

इनमें केरल के विभिन्न जिलों में स्थित इमारतें और जमीन शामिल हैं जिनका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए होता था। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और दोषसिद्धि भी हुई। यह दिखाता है कि संगठनात्मक स्तर पर आर्थिक कार्रवाई संभव और प्रभावी है किंतु इसे और आगे ले जाना होगा। हर दोषसिद्ध सदस्य की व्यक्तिगत संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए । तभी संदेश साफ जाएगा कि आतंक की कीमत न सिर्फ जेल है बल्कि पूरी कमाई और जायदाद भी है। जम्मू-कश्मीर में हाल के महीनों में कई ठोस उदाहरण सामने आए हैं। रियासी जिले में पाकिस्तान में बैठे पांच आतंकियों की लगभग 27 से 29 कनाल जमीन यूएपीए की धारा 25 के तहत अटैच की गई। ये लोग वर्षों पहले पाकिस्तान चले गए थे और अब अपनी संपत्ति बेचकर आतंक की फंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे। रामबन और अन्य जिलों में भी पाक आधारित आतंकियों की संपत्तियां अटैच हुई हैं। ये कदम सही दिशा में हैं परन्तु अटैचमेंट के बाद संपत्ति बेचकर रकम खजाने में जमा करने का प्रावधान लागू होना चाहिए। जमीन-जायदाद दोबारा आतंक की पूंजी न बने, इसके लिए यह कदम अनिवार्य है। भारतीय मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा और आईएसआईएस मॉड्यूल के सदस्यों के खिलाफ देशभर में सैकड़ों मामले चले हैं। एनआईए की सजा दर ऊंची रही है। कई आरोपियों पर बम विस्फोट, भर्ती, फंडिंग और साजिश के आरोप साबित हुए। फिर भी उनकी संपत्तियों पर पूरी कार्रवाई हमेशा नहीं होती। कई बार खाते फ्रीज होते हैं लेकिन बिक्री और खजाने में जमा करने तक मामला नहीं पहुंचता। आतंकवादी और उनके संगठन धन से मजबूत होते हैं। जब धन छीन लिया जाता है तो संगठन बिखरते हैं, भर्ती रुकती है, प्रचार कम होता है और परिवार भी सहयोग करने से हिचकते हैं। दूसरी ओर सरकारी खजाने में रकम जमा होने से दो फायदे होते हैं। एक तो आतंक की पूंजी नष्ट होती है, दूसरा वह रकम राष्ट्र-निर्माण या पीड़ितों के मुआवजे में इस्तेमाल हो सकती है। अत: इस संबंध में वर्तमान की आवश्यकता है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक समर्पित इकाई हो जो दोषसिद्ध आतंकियों की संपत्तियों की सूची बनाए, जब्ती करे, बिक्री की प्रक्रिया पूरी करे और रकम खजाने में जमा करे। जाकिर नाइक के आईआरएफ पर राज्यों को दिए गए अधिकार को आधार बनाकर सिमी, पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन और अन्य संगठनों पर भी समान व्यवस्था लागू की जाए। जिन सदस्यों पर न्यायालय ने सजा सुनाई है, उनके बैंक खातों में पड़ी हर राशि, उनके नाम की हर संपत्ति जब्त हो। अब जब आतंकवादी यह जान जाएंगे कि पकड़े जाने और दोषसिद्धि के बाद उनकी पूरी कमाई, जमीन-जायदाद और बैंक बैलेंस सरकारी खजाने में चली जाएगी, तब भर्ती और सहयोग दोनों में कमी आएगी। केंद्र का आईआरएफ वाला फैसला इसी दिशा का सही संकेत है। आगे इसे हर स्तर पर लागू करना होगा। सिमी हो, जाकिर नाइक का आईआरएफ हो, पीएफआई हो या जम्मू-कश्मीर के पाक-आधारित आतंकी, सभी के साथ एक ही नियम हो। दोषसिद्ध आतंकवादी की संपत्ति जब्त करो, बेचो और सरकारी खजाने में डालो। वास्तव में यही आतंक पर असली कड़ी कार्रवाई होगी और यही देश की सुरक्षा की व्यवहारिक मांग भी है।

संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक है। यहां होने वाले फैसले केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की राजनीतिक लड़ाई नहीं होते, बल्कि वे करोड़ों नागरिकों के भविष्य से जुड़े होते हैं। इसलिए संसद के विशेष सत्र में प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधायी कदमों की जानकारी जनता को पहले से मिलनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही केवल संसद के भीतर नहीं, बल्कि देश की जनता के प्रति भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जैसे व्यापक प्रभाव वाले मुद्दे को पर्याप्त सार्वजनिक विमर्श के बिना आगे बढ़ाया जाना उचित है? महिला सशक्तीकरण का समर्थन पूरे देश को करना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर किसी भी संवैधानिक बदलाव के संभावित परिणामों पर सवाल उठाना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। परिसीमन का विषय बेहद संवेदनशील है। देश की आबादी, राज्यों की जनसंख्या, संसदीय प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर ही इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। यदि लोकसभा की सीटों में भारी वृद्धि की जाती है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इससे संसद की कार्यक्षमता, सरकारी खर्च और आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है।

अलविदा लोकतंत्र !

सत्ता की राजनीति, परिसीमन की आशंकाएं और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बड़ा सवाल



शबाना बेगम,
वरिष्ठ पत्रकार



लोकतंत्र केवल चुनाव कराने और बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की भागीदारी, उसकी स्वतंत्र आवाज, विपक्ष की भूमिका और सत्ता से सवाल पूछने के अधिकार में निहित होती है। लेकिन जब सत्ता में बैठी सरकार महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक फैसलों को जनता की जानकारी तथा व्यापक चर्चा से दूर रखने का प्रयास करती दिखाई दे, तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर उठ रही राजनीतिक बहस ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय को परिसीमन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के राजनीतिक और संवैधानिक प्रभावों पर देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए। आखिर यह फैसला केवल संसद की सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राज्यों के बीच संतुलन और भविष्य की चुनावी व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक है। यहां होने वाले फैसले केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की राजनीतिक लड़ाई नहीं होते, बल्कि वे करोड़ों नागरिकों के भविष्य से जुड़े होते हैं। इसलिए संसद के विशेष सत्र में प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधायी कदमों की जानकारी जनता को पहले से मिलनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही केवल संसद के भीतर नहीं, बल्कि देश की जनता के प्रति भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जैसे व्यापक प्रभाव वाले मुद्दे को पर्याप्त सार्वजनिक विमर्श के बिना आगे बढ़ाया जाना उचित है? महिला सशक्तीकरण का समर्थन पूरे देश को करना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर किसी भी संवैधानिक बदलाव के संभावित परिणामों पर सवाल उठाना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। परिसीमन का विषय बेहद संवेदनशील है। देश की आबादी, राज्यों की जनसंख्या, संसदीय प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर ही इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। यदि लोकसभा की सीटों में भारी वृद्धि की जाती है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इससे संसद की कार्यक्षमता, सरकारी खर्च और आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। वह अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को देता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि संसद में सांसदों की संख्या बढ़ाने से आम जनता को क्या ठोस लाभ मिलेगा? क्या अधिक सांसद होने से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? क्या अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध हो जाएगा? क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी? क्या महंगाई पर नियंत्रण हो सकेगा? संसद में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने की गारंटी नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती प्रतिनिधियों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता के प्रति संवेदनशीलता से तय होती है। यह भी जरूरी है कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी राज्य के साथ अन्याय न हो। भारत विविधताओं वाला संघीय देश है। अलग-अलग राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में अलग-अलग परिस्थितियों में काम किया है। ऐसे में केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का नया संतुलन तैयार करना दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों के बीच राजनीतिक असंतुलन की आशंका पैदा कर सकता है। इस विषय पर सभी राज्यों और राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।

सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता। विपक्ष जनता की दूसरी आवाज है। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि किसी संवैधानिक बदलाव को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, तो उसका जवाब तथ्यों, तर्कों और पारदर्शी चर्चा से दिया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव अथवा सत्ता के प्रभाव से। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सत्ता की राजनीति लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर हो सकती है? क्या बहुमत के नाम पर हर फैसला उचित ठहराया जा सकता है? क्या जनता को केवल चुनाव के समय याद किया जाएगा और उसके बाद उसके अधिकारों तथा सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसे याद रखना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं और संवैधानिक मूल्य देश की स्थायी धरोहर हैं। किसी भी सरकार को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिनसे जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कमजोर हो। हमारा स्पष्ट मत है कि महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक भागीदारी देना होना चाहिए, न कि उसे किसी राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाना। परिसीमन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संघीय ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए। संसद की सीटों में वृद्धि हो या कोई अन्य संवैधानिक परिवर्तन, उसके हर पहलू पर देश के नागरिकों को जानकारी और अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। आखिर में महात्मा गांधी के विचारों को याद करना जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने देशवासियों को निर्भीक होकर आजादी के संघर्ष में भाग लेने का संदेश दिया था। उनका संघर्ष केवल विदेशी शासन से मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए भी था जहां जनता की आवाज सर्वोपरि हो। लोकतंत्र किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता का अधिकार, जनता की ताकत और जनता की अमानत है। इसे बचाना केवल विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है।

सद्भावना टुडे का संपादकीय संदेश: सत्ता से सवाल पूछना लोकतंत्र विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है।

विचार

बल्ले से निकला वैभव, क्रिकेट के आकाश में नया सूर्य

ललित गर्ग

क्रिकेट के इतिहास में कुछ दिन केवल कैलेंडर की तारीख बनकर नहीं आते, वे इतिहास के पन्नों पर अमिट हस्ताक्षर कर जाते हैं। मंगलवार का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा ही एक मंगलमय दिवस बनकर सामने आया, जब महज पंद्रह वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने दोहा में अपने बल्ले से ऐसा सूर्य उदय किया, जिसकी रोशनी ने पूरी क्रिकेट दुनिया को चकाचौंध कर दिया। जिस उम्र में किशोर सपनों की उड़ान भरना शुरू करते हैं, उस उम्र में वैभव ने क्रिकेट के आकाश में अपने नाम का ऐसा ध्वज फहरा दिया, जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। वैभव ने केवल 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया। 28 गेंदों में शतक, महज 40 गेंदों में 150 रन और एक पारी में 28 छक्के-ये आंकड़े किसी वीडियो गेम की काल्पनिक स्कोरशीट जैसे लगते हैं, लेकिन वैभव ने इन्हें हकीकत की पिच पर उतार दिया। सूर्यवंशी की इस आतिशी पारी से दुनिया में खलबली मच गयी है, देश और दुनिया में बड़ी-बड़ी खबरों को दबा दिया है इस खबर ने। आज दुनिया के क्रिकेट जगत में सूर्यवंशी के खेल-वैभव की चर्चा हर जबान पर है। क्रिकेट के दिग्गज उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि उन्हें टी-20 व वन डे की भारतीय टीम में बतौर ओपनर कब जगह मिल पायेगी? 204 रनों की उनकी तूफानी पारी में 168 रन केवल छक्कों से आए। बल्ले से निकली हर गेंद मानो सीमा रेखा के पार जाकर एक नया इतिहास लिख रही थी। यह केवल रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि क्रिकेट की सीमाओं को चुनौती देने वाली एक अद्भुत बल्लेबाजी थी।

भारतीय क्रिकेट ने समय-समय पर ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने दुनिया को भारतीय क्रिकेट का लोहा मनवाया।

सुनील गावस्कर की तकनीक, कपिल देव का साहस, सचिन तेंदुलकर की विलक्षणता, सौरव गांगुली का आत्मविश्वास, महेंद्र सिंह धोनी की निर्णायक क्षमता और विराट कोहली की आक्रामक निरंतरता-इन सबने भारतीय क्रिकेट को गौरव दिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि यह कहानी अभी किशोरावस्था में ही असाधारण उपलब्धियों का शंखनाद कर रही है। वैभव का बल्ला इस समय केवल गेंद को नहीं पीट रहा, बल्कि क्रिकेट की पुरानी धारणाओं को भी चुनौती दे रहा है और अपने कीर्तिमान से नया इतिहास बना रहा है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास है, निर्भीकता है, आक्रामकता है और सबसे बढ़कर एक स्वाभाविक लय है। वे गेंदबाज के नाम, प्रतिष्ठा या अनुभव से भयभीत होते दिखाई नहीं देते। उनकी बल्लेबाजी देखकर लगता है कि गेंद उनके लिए चुनौती नहीं, अवसर है और सीमा रेखा उनके लिए कोई दीवार नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों की फेहरिस्त भी कम चमत्कारी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में दस मैचों में 185 के स्ट्राइक रेट से 295 रन और आईपीएल की 23 पारियों में 228 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 1028 रन उनकी असाधारण क्षमता का प्रमाण हैं। आईपीएल के 2026 सत्र में 72 छक्के लगाकर उन्होंने एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा और ऑरेंज कैप हासिल की। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां निश्चित रूप से सामान्य प्रतिभा की निशानी नहीं हैं। दोहा की इस पारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वैभव को भारतीय वनडे और टी-20 टीम में अवसर कब मिलेगा। यह स्वाभाविक मांग है कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर आजमाया जाए, लेकिन इसके साथ धैर्य और विवेक भी जरूरी है। प्रतिभा को अवसर चाहिए, पर अवसर के साथ संरक्षण, मार्गदर्शन और मानसिक तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। क्रिकेट केवल बल्ले की ताकत का खेल नहीं, बल्कि परिस्थितियों, दबाव, रणनीति और मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा है। सोलह वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतारने का उदाहरण आज भी प्रेरणा देता है। सचिन ने उस अवसर को इतिहास में बदल दिया। वैभव के सामने भी संभावनाओं का विराट आकाश है। उन्हें अवसर अवश्य मिलने चाहिए, लेकिन उनके क्रिकेटीय विकास की गति और दिशा को समझते हुए। भारतीय क्रिकेट प्रशासन के लिए यह एक ऐसी प्रतिभा है, जिसे जल्दबाजी में दबाव के हवाले करने के बजाय सही ढंग से तराशने की जरूरत है। आज दुनिया के गेंदबाज भी वैभव की बल्लेबाजी को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। उनकी कमजोरियां तलाशने, उनकी हिटिंग पावर को रोकने और उनके आक्रामक तेवरों पर अंकुश लगाने की रणनीतियां बन रही होंगी। यही चुनौती वैभव के लिए अगला पड़ाव है। उन्हें अपनी तकनीक में विविधता, शॉट चयन में परिपक्वता और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करने की क्षमता विकसित करनी होगी। क्योंकि क्रिकेट में असली महानता केवल रिकॉर्ड बनाने में नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बनने के बाद भी निरंतर ऊंचाई पर टिके रहने में है।

एक नजर

नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी निगरानी, हॉटस्पॉट और तस्करी मार्ग होंगे चिह्नित



सुपौल। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर शनिवार को (नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर) की बैठक आयोजित की गई। कार्यालय वेश्म में उप विकास आयुक्त-सह-प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की गई। साथ ही नशामुक्ति एवं जनजागरूकता से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करें और जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार से जुड़े हॉटस्पॉट और तस्करी मार्गों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया, ताकि ऐसे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बैठक के दौरान मासिक प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ नशामुक्ति और जनजागरूकता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला वन प्रमंडल कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विशेष शाखा, मद्यनिषेध विभाग, जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, औषधि निरीक्षक, जिला सामान्य शाखा के पदाधिकारी सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। पटना से एनसीबी के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

संस्कृत विश्वविद्यालय का आठवां दीक्षांत समारोह 5 दिसंबर को, 39 पीजी विद्यार्थियों को मिलेगा गोल्ड मेडल

दरभंगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आठवें दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 5 दिसंबर को शिक्षा शास्त्र विभाग परिसर में आयोजित होने वाले इस समारोह में कुलाधिपति सह बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन अध्यक्षता करेंगे। समारोह में 39 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। समारोह के आयोजन को लेकर लोक भवन, पटना की ओर से मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम एवं मंचीय आसन व्यवस्था को स्वीकृति मिल चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुलाधिपति सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे। इसके 20 मिनट बाद सुबह 11:50 बजे शोभायात्रा के साथ दीक्षांत समारोह की औपचारिक शुरुआत होगी। इस अवसर पर कुलपति प्रो. लक्ष्मी निवास पांडेय स्वागत भाषण देंगे तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं संस्थागत प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। भारतीय भाषा समिति, नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं पद्मश्री सम्मानित चामू कृष्ण शास्त्री दीक्षांत भाषण देंगे। वहीं बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी समारोह को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12:48 बजे दीक्षा वाक्य एवं शपथ का आयोजन होगा। इसके बाद कुलाधिपति 39 स्नातकोत्तर गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ताओं को शुभकामनाएं देंगे। राज्यपाल का अध्यक्षीय संबोधन दोपहर 1:10 बजे निर्धारित है। समारोह की औपचारिक गतिविधियां पूरी होने के बाद भोजन की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार कुलाधिपति अपराह्न 2:05 बजे पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार दीक्षांत समारोह में उनकी कुल 2 घंटे 35 मिनट की उपस्थिति निर्धारित की गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह को लेकर विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं विश्वविद्यालय परिवार में उत्साह है। विशेष रूप से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अवसर उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के सार्वजनिक सम्मान का महत्वपूर्ण क्षण होगा।

निर्वाचन साक्षरता प्रतियोगिता में बक्सर और राजपुर के 20 प्रतिभागियों ने मारी बाजी

बक्सर। युवा एवं भावी मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को नगर परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में विधानसभा स्तरीय निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 200-बक्सर एवं 202-राजपुर (अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) से चयनित प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। दोनों विधानसभा क्षेत्रों से निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता में पांच-पांच प्रतिभागियों का चयन किया गया।प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों की निर्वाचन प्रक्रिया, मताधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदाता के अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित जानकारी का आकलन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने लोकतंत्र एवं निर्वाचन से जुड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, जबकि क्विज के जरिए निर्वाचन संबंधी उनके ज्ञान की परख की गई।

बक्सर विधानसभा क्षेत्र की निबंध प्रतियोगिता में प्रगति कुमारी, तब्बसुन खातून, लक्ष्मी कुमारी, शांति कुमारी एवं अपराजिता कुमारी ने सफलता हासिल की। वहीं क्विज प्रतियोगिता में अंकित कुमार, यासयीन, अभिनव कुमार, अनीश कुमार एवं यासयीन खातून सफल रहे। इसी तरह राजपुर विधानसभा क्षेत्र की निबंध प्रतियोगिता में कल्पना कुमारी, रिया दुबे, स्वेच्छा कुमारी, पलक कुमारी एवं दीपशिखा कुमारी ने स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में तनु कुमारी, आदर्श कुमार, चंदन कुमार, हिमांशु कुमार एवं अनामिका राज सफल प्रतिभागियों में शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम की शुद्धता, मतदान का महत्व, मतदाता के अधिकार एवं दायित्व तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के संबंध में जानकारी दी गई। आयोजकों ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जागरूक मतदाताओं की भागीदारी जरूरी है। निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने और उनमें स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नैतिक मतदान की भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नियमानुसार प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जागरूक मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला हैं।

बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है : मुख्यमंत्री



पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा, संस्कृति और एकता के उत्सव के रूप में पटना के बापू सभागार में आज से तीन दिवसीय आठवें 'डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चों को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, इसके लिए प्रदेश में ही बेहतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने डीएवी संस्थान के अध्यक्ष डॉ पूनम सूरी से आग्रह करते हुये कहा कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार की सभी पुलिस लाइनों में डीएवी स्कूल खोलें। उन्होंने इसके लिए सभी चिह्नित स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग डेढ़ लाख पुलिस बल हैं, जिनमें करीब 40 हजार महिला पुलिसकर्मी हैं।उन्होंने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और अगले एक साल में इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए बिहार की विशिष्ट पहचान रही है। बिहार ने देश को स्वर्णिम काल दिया है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय इसी पावन धरती पर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित डीएवी संस्थान पिछले 140 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्ष 1886 में लाहौर से शुरू हुई इस शैक्षणिक यात्रा ने आज देशभर में हजारों संस्थानों का स्वरूप ले लिया है। बिहार के लाखों बच्चे डीएवी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 534 प्रखंडों सहित 700 स्थानों पर सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है, जहां लगभग 4.5 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तकनीक के माध्यम से बच्चों को हर समय शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 से 2026 तक बिहार में मात्र 272 डिग्री कॉलेज थे। वर्तमान में राज्य सरकार ने एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही उनमें शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की लगभग 62 प्रतिशत आबादी 29 वर्ष से कम उम्र की है। प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 18 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध करा रही है। बड़ी संख्या में बिहार के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। सरकार का प्रयास है कि बिहार में ही ऐसे शैक्षणिक संस्थान विकसित हों, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास किया गया है। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया में हवाई सेवाओं के विस्तार के साथ प्रदेश में 10 नए हवाई अड्डों के निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 प्रतिशत के ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री का विकास हो रहा है।

परिसीमन बिल के विरोधियों को महिला विरोधी समझा जाएगा : गिरिराज



भागलपुर। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार को भागलपुर में परिसीमन विधेयक को देश और लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान आज उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से महिला आरक्षण के साथ-साथ लोकसभा सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान उन्होंने विधेयक का विरोध कर रहे विपक्षी दलों और नेताओं पर तीखा हमला बोला। विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'आखिर लोग परिसीमन को लेकर इतना हाय-तौबा क्यों मचा रहे हैं?

इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं।' उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह मॉडल दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के लिए भी उतना ही बेहतर है और जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें महिला विरोधी समझा जाएगा। सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत को समझाते हुए गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बेगूसराय की आबादी करीब 40 लाख है, जिसमें 22 से 23 लाख मतदाता हैं। इतनी बड़ी आबादी और विशाल क्षेत्रफल के कारण एक सांसद के लिए हर गांव तक पहुंच पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व को प्रभावी बनाने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ये लोग भारत विरोधियों की 'टूलकिट' बन गए हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा परिसीमन बिल को बीजेपी की भूल बताए जाने पर उन्होंने कड़ा पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जनता और विद्यार्थियों से किए गए वादों को याद करना चाहिए और उन्हें पूरा न करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। स्थानीय अंदाज में तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अपन ब्याह नहीं, सूरदास के बरतुहारी करे चलल हैं।'

रामरेखा घाट समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर जांच अभियान में एक अनिबंधित नाव जब्त

बक्सर। गंगा नदी में जल यातायात को सुरक्षित बनाने और श्रद्धालुओं व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को रामरेखा घाट समेत शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर अवैध एवं अनिबंधित नावों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय की टीम ने जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमानिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान बिना वैध निबंधन और आवश्यक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर परिचालित की जा रही एक नाव को जब्त किया गया।

जांच अभियान के दौरान नावों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाण पत्र, नाविकों के लाइसेंस तथा सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जांच की गई। इसमें लाइफ जैकेट समेत अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की स्थिति भी देखी गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नाव को परिवहन विभाग के निर्देश पर नगर परिषद की ओर से तत्काल जब्त कर लिया गया। वहीं, नाव स्वामी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने नाव मालिकों और नाविकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना वैध निबंधन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र के गंगा नदी में नावों का परिचालन नहीं करें। निबंधन के लिए अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देने को कहा गया है। नावों पर निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर भी रोक लगाई गई है।

प्रत्येक नाव में पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट, रस्सी और अन्य जीवन रक्षक उपकरण रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा नाव संचालन के लिए नाविकों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है। अप्रशिक्षित या नाबालिग व्यक्तियों से नाव नहीं चलवाने तथा सूर्यास्त के बाद और तेज हवा या कोहरे जैसी खराब मौसम की स्थिति में नाव परिचालन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि गंगा घाटों पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और जल मार्ग से यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए नगर परिषद एवं अंचल कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय अंग्रेजी शिक्षक सम्मेलन में डॉ. युगेश्वर साह की दो पुस्तकों का लोकार्पण



दरभंगा,एजेंसी। अकादमिक शोध और साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में सीएम साइंस कॉलेज, दरभंगा के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. युगेश्वर साह ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में आयोजित 69वें ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर्स कांफ्रेंस में उनकी दो पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। 26 से 28 नवंबर तक आयोजित इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से आए अंग्रेजी के शिक्षकों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों की उपस्थिति में पुस्तकों का विमोचन हुआ। डॉ. साह की पहली पुस्तक अनुवाद अध्ययन के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों पर केंद्रित अकादमिक संकलन है। जयपुर के वाईकिंग बुक्स से प्रकाशित इस पुस्तक में अनुवाद की विभिन्न अवधारणाओं, पद्धतियों और चुनौतियों पर आधारित 21 शोध आलेखों के साथ एक पुस्तक समीक्षा भी शामिल है। यह संकलन अनुवाद के क्षेत्र में अकादमिक विमर्श को समृद्ध करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनकी दूसरी पुस्तक 'द कॉन्टेस्ट ऑफ लाइफ' मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार जगदीश प्रसाद मंडल के चर्चित मैथिली कहानी-संग्रह 'प्रतिस्पर्धा' का अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें मूल संग्रह की दस कहानियों को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से डॉ. साह ने मैथिली की समृद्ध कथा परंपरा को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इन कहानियों में मिथिला के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन, लोकचेतना, जीवन-दर्शन और समाज के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों का जीवंत चित्रण मिलता है। अंग्रेजी अनुवाद के जरिए मैथिली समाज और साहित्य की संवेदनाओं को दूसरी भाषा के पाठकों के सामने रखने का अवसर मिला है। यह पहल क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को व्यापक साहित्यिक संसार से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

एक ही राष्ट्रीय मंच पर अनुवाद अध्ययन से संबंधित शोध संकलन और मैथिली कथा साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण डॉ. साह की अकादमिक एवं साहित्यिक सक्रियता को रेखांकित करता है। इस उपलब्धि पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. संजीव कुमार मिश्र सहित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. युगेश्वर साह को बधाई दी है।

महाराजा कामेश्वर सिंह की जयंती पर सेवा और स्मरण का आयोजन, दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण की उठी मांग



दरभंगा,एजेंसी। मिथिला के ऐतिहासिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महाराजाधिराज डॉ. सर कामेश्वर सिंह की 119वीं जयंती पर कामेश्वर नगर स्थित महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। जयंती समारोह में जहां उनके ऐतिहासिक योगदान पर चर्चा हुई, वहीं जनसेवा के माध्यम से उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया। इस अवसर पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग भी प्रमुखता से उठी।

राज दरभंगा एवं कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के ट्रस्टी कुमार राजेश्वर सिंह और कुमार कपिलेश्वर सिंह के सानिध्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ महाराजा के तैलचित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि महाराजा कामेश्वर सिंह का व्यक्तित्व केवल राजशाही तक सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, विमानन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिथिला में शैक्षणिक संस्थानों और शोध की परंपरा को मजबूत करने में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। वक्ताओं ने भूदान आंदोलन में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने विनोबा भावे के आंदोलन के दौरान करीब 1.17 लाख एकड़ भूमि दान की थी। उनका जीवन समाज के प्रति उदारता, शिक्षा के प्रसार और जनकल्याण की भावना का उदाहरण रहा है। जयंती के अवसर पर आयोजित चिकित्सा शिविर में लगभग 250 मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। डीएमसीएच एवं राज अस्पताल के चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित किए गए। इस पहल को महाराजा की जनसेवा और परोपकार की परंपरा से जोड़कर देखा गया। कार्यक्रम के दौरान राजीव प्रकाश मधुकर, विजय कुमार पासवान सहित अन्य लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराजाधिराज डॉ. सर कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग उठाई। वक्ताओं का कहना था कि मिथिला के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए हवाई अड्डे का नामकरण उनके नाम पर किया जाना चाहिए। इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए आगामी 6 दिसंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को प्रस्ताव सौंपने की बात कही गई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संतोष कुमार ने किया। आयोजन को सफल बनाने में राज दरभंगा के मुख्य प्रबंधक सह राज अस्पताल के सचिव आशुतोष दत्ता, पूर्व भू-संपदा पदाधिकारी कर्म नाथ सिंह ठाकुर, रामकृष्ण लाल दास, मुरली जी, छात्र नेता उत्सव पारासर, जितेंद्र ठाकुर, संतोष सिंह, बबलु त्रिगुणायत, सुनील रॉय, राजू मंडल, दीपक, नीरज, अमरकांत झा, बुचुन, खुशबू कुमारी, संतोष झा, नीतीश, अशोक कुमार मंडल सहित सैकड़ों लोगों की सहभागिता रही।

लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर इंडी गठबंधन अराजकता का पोषक : अनुराग ठाकुर

पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को बिहार के आरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी पराजय स्वीकार करने के बजाय लगातार संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर देश में भ्रम और अविश्वास का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद बिहार और केरल सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं। यदि कांग्रेस ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री चुनाव परिणामों को लेकर क्या रुख अपनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर भारत की लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

भाजपा सांसद ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक का मताधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूचियों को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। विपक्ष की ओर से इसे वोट चोरी बताना तथ्यों से परे है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'यह वोट चोरी नहीं, बल्कि चोरों को वोट मिलना बंद हो गया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से निवास बदल चुके लोगों, अनुपस्थित मतदाताओं और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों का सत्यापन निर्वाचन प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एसआईआर के तीन चरणों में लगभग 95.40 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। इनमें 13.39 करोड़ मतदाताओं को एएसडीडी और अन्य श्रेणियों में चिह्नित किया गया। उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी व्यक्ति का निधन हो चुका है, कोई स्थायी रूप से अपना निवास बदल चुका है या एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर दर्ज है तो ऐसी प्रविष्टियों को मतदाता सूची में बनाए रखने का क्या औचित्य है? राहुल गांधी की राजनीति पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने विदेशी धन, विदेशी मित्रों और विदेशी ताकतों के सहारे देश में राजनीतिक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताना देश की आर्थिक उपलब्धियों को नजरअंदाज करने जैसा है। भाजपा सांसद ने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए हुए है।

एक नजर

विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल ने जीता 20वीं यश हॉस्पिटल ट्रॉफी का उद्घाटन मुकाबला



प्रयागराज,एजेंसी। विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल क्रिकेट अकादमी ने शनिवार को एएस हनुमानगंज क्लब को दस रन से हराकर 20वीं यश हॉस्पिटल ट्रॉफी अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला अपने नाम किया। शुआट्स मैदान पर शनिवार को खेले गए मुकाबले में विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में आठ विकेट पर 170 रन (ध्रुव 48 नाबाद, प्रखर 31, आदित्य सिंह 24, आर्यन सिंह यादव 20, अथर्व 4/26, मयंक यादव 2/18) बनाए। जवाब में एएस हनुमानगंज क्लब की टीम 28.4 ओवर में 160 रन (प्रशांत गुप्ता 41, अंशु विश्वकर्मा 29, कार्तिकेय राय 24, प्रतीक यादव 15, अरुणभ दयाल 3/18, शुभम पाल 3/29 निर्भय 2/26) पर सिमट गई। इससे पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन शुआट्स के उप निदेशक मजिद खान एवं यश हॉस्पिटल के प्रशासनिक प्रबंधक पंकज सेठ ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। आयोजन सचिव परवेज आलम ने बुके देकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद जेब फारान ने किया। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार, अशफाक अहमद, राकेश यादव, मोहम्मद असलम, मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे।

राज्य स्तरीय रोल बॉल चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए मुरादाबाद की रोल बॉल टीम रवाना



मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के बावनवाड़ी इंटरनेशनल स्कूल में 29, 30 नवंबर और 01 दिसंबर को होने वाली राज्य स्तरीय रोल बॉल चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए मुरादाबाद की टीम शनिवार दोपहर 12 बजे डीपीएस से शिवम कुमार की कप्तानी में रवाना हुई। चैम्पियनशिप से पहले चयनित खिलाड़ियों का 07 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। शिविर में खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों, टीम समन्वय, स्टैमिना और फिटनेस का गहन अभ्यास कराया गया, जिससे टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयार हो सके। टीम की रवानगी के अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य सुदर्शन सोनार, प्रो वाइस चेयरमैन संदीप जैन और नितिन जैन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन और टीम भावना के साथ खेलने की सलाह दी और कहा कि वे अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से जीत हासिल कर जनपद और विद्यालय का नाम रोशन करें। डिस्ट्रिक्ट रोल बाल एसोसिएशन मुरादाबाद की सचिव रिम्पी सिंह, अध्यक्ष मनु मिश्रा, कोषाध्यक्ष लियाकत अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परमेश्वरन और मधुरेंद्र कुमार, मनी शर्मा तथा गौरव कुमार सहित एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने भी टीम को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद लेंगे संन्यास



ढाका। बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम इंग्लैंड के खिलाफ अगले साल फरवरी में मीरपुर में होने वाले पहले टेस्ट मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने शनिवार को उनके संन्यास के फैसले की जानकारी दी। इसके साथ ही 39 वर्षीय मुशफिकुर का 21 साल से अधिक लंबा अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो जाएगा। मुशफिकुर पहले ही एकदिवसीय और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ पहला मुकाबला उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। तमीम इकबाल ने बताया कि मुशफिकुर ने कुछ दिन पहले फोन पर उन्हें अपने फैसले की जानकारी दी थी। इकबाल ने उनसे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संन्यास की घोषणा करने को कहा था, लेकिन उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष से ही इसकी जानकारी सार्वजनिक करने का आग्रह किया। इकबाल ने मुशफिकुर की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि वह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए लंबे समय तक समर्पित भाव से खेलने वाले महान खिलाड़ी रहे हैं। मुशफिकुर बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर हैं। उन्होंने अब तक 108 टेस्ट मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है और तीन दोहरे शतक लगाए हैं। हाल ही में वह टेस्ट क्रिकेट में सात हजार रन पूरे करने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज भी बने। उनका संन्यास बांग्लादेश क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत होगा। दो दशक से अधिक के करियर में उन्होंने टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देने के साथ कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर टेस्ट के साथ वह अपने लंबे टेस्ट सफर को विराम देंगे।

भारतीय महिला हॉकी टीम लगातार चौथी बार बनी एशियन चैंपियन, रचा इतिहास

भोपाल,एजेंसी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब चौथी बार अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नाथूखेड़ा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 3-1 से पराजित किया। भारत की इस खिताबी जीत में दीपिका ने दो गोल किए, जबकि इशिका ने एक गोल दागा। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक चार बार खिताब जीतने वाली टीम बन गई।

फाइनल मुकाबले में चीन ने पहले गोल कर भारतीय टीम पर दबाव बना दिया था। चीन की चेन युजुन ने 24 मिनट 55 सेकेंड में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ तक भारतीय टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी। हालांकि, तीसरे क्वार्टर में भारत ने जोरदार वापसी की। दीपिका ने 37 मिनट 50 सेकेंड में गोल कर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके करीब सवा तीन मिनट बाद इशिका ने 41 मिनट 15 सेकेंड में गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। इसके तुरंत बाद 42 मिनट 25 सेकेंड में दीपिका ने अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को वापसी का मौका नहीं दिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। शानदार खेल के लिए दीपिका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने लगातार चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने की उपलब्धि भी हासिल की। भारत ने इससे पहले 2016, 2023 और 2024 में



ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। वहीं दक्षिण कोरिया भी तीन बार इस प्रतियोगिता का विजेता रहा है। चौथे खिताब के साथ भारत अब टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गया है। भारतीय टीम का प्रदर्शन प्रतियोगिता में शुरू से ही दमदार रहा। लीग चरण में उसने मलेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, चीन और जापान को हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। इसके बाद सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में दीपिका ने दो गोल किए थे। मुमताज खान, नवनीत कौर, सुनेलिता टोप्पो और इशिका ने भी एक-एक गोल कर जीत में योगदान दिया था। दूसरी ओर चीन ने जापान को 1-0 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। खिताबी मुकाबले में भी भारतीय टीम ने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए बिना कोई मैच गंवाए ट्रॉफी जीत ली। जीत के बाद भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि चीन के शुरुआती गोल के बाद भी खिलाड़ियों ने धैर्य नहीं खोया। पूरी टीम को भरोसा था कि वे मुकाबले में वापसी कर सकती हैं। खिलाड़ियों के बीच एक-दूसरे पर विश्वास का ही नतीजा रहा कि टीम ने लगातार तीन गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। सलीमा ने भारतीय धरती पर खिताब जीतने को पूरे देश के लिए गर्व का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है और आगामी प्रतियोगिताओं में इससे बेहतर करने का प्रयास रहेगा। फिलहाल खिलाड़ी आराम करेंगी और इसके बाद हॉकी इंडिया लीग पर ध्यान देंगी।

अंशुल मिश्रा ने लगातार दूसरी बार जीता गुजरात एमेच्योर गोल्फ खिताब

चंडीगढ़। राउंडग्लास गोल्फ अकादमी के खिलाड़ी अंशुल मिश्रा ने इंडियन गोल्फ यूनियन (आईजीयू) गुजरात एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के कलहार ब्लूज एंड ग्रीन्स गोल्फ क्लब में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत के नंबर एक रैंकिंग वाले एमेच्योर गोल्फर अंशुल ने अंतिम दिन शानदार वापसी करते हुए एक शॉट के अंतर से जीत दर्ज की। 72 होल की प्रतियोगिता में अंशुल ने कुल तीन ओवर 291 का स्कोर बनाया। उनका चार दौर का स्कोर 72, 75, 75 और 69 रहा। उन्होंने चंडीगढ़ के नील जॉली को एक शॉट से पीछे छोड़ते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। लगातार दो दौर में 75 का स्कोर करने के बाद अंशुल चौथे और निर्णायक दौर में शीर्ष खिलाड़ियों से पीछे चल रहे थे। हालांकि, अंतिम दिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और तीन अंडर 69 का कार्ड खेला। यह प्रतियोगिता का संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर था। सटीक शॉट और एकाग्रता के दम पर उन्होंने अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब जीत लिया। नील जॉली चार ओवर 292 के कुल स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उनका चार दौर का स्कोर 78, 72, 71 और 71 रहा। कर्नाटक के तनीष आर. गौड़ा सात ओवर 295 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने चार दौर में 76, 70, 80 और 69 का स्कोर किया। हरियाणा के नवीन राठी नौ ओवर 297 के कुल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। उनका स्कोर 69, 76, 74 और 78 रहा। इस जीत के साथ अंशुल ने गुजरात एमेच्योर चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने 2025 में केन्सविले गोल्फ रिसॉर्ट में तीन अंडर 285 के शानदार स्कोर के साथ यह खिताब अपने नाम किया था। अंशुल के लिए यह जीत 2026 के शानदार सत्र का एक और बड़ा पड़ाव है। इससे पहले वह इसी साल आईजीयू नॉर्दर्न इंडिया एमेच्योर और आईजीयू आंध्र प्रदेश एमेच्योर चैंपियनशिप के खिताब भी जीत चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को राउंडग्लास गोल्फ अकादमी की उच्चस्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था का परिणाम बताया गया है। अकादमी में तकनीकी प्रशिक्षण के साथ खेल विज्ञान और मानसिक मजबूती पर भी ध्यान दिया जाता है। राउंडग्लास गोल्फ अकादमी का लक्ष्य देश की प्रतिभाशाली गोल्फ खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना और इस खेल में नए मानक स्थापित करना है।

देवरिया की काजल पासवान का अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयी एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए चयन



देवरिया। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के संत विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया की प्रतिभाशाली छात्रा काजल पासवान ने अपनी मेहनत, लगन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा काजल का चयन 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयी एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भुवनेश्वर में आयोजित होगी। काजल के चयन से महाविद्यालय और जनपद में खुशी का माहौल है। काजल पासवान ने 23 से 25 नवंबर तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ को 1:28:06 घंटे के रिकॉर्ड समय में पूरा किया। उनके इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। काजल ने अपनी उपलब्धि से महाविद्यालय के साथ ही जनपद देवरिया का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उनकी लगातार सफलता खेल के प्रति समर्पण, अनुशासन और कठिन परिश्रम का परिणाम है। महाविद्यालय के प्रबंधक अशोक कुमार मिश्र, प्राचार्य प्रो. अर्जुन मिश्र, शिक्षकगण और कर्मचारियों ने काजल पासवान को बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। व्यायाम शिक्षक डॉ. मंतोष कुमार मौर्य ने बताया कि काजल ने पूर्व में भी कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर महाविद्यालय और जिले को गौरवान्वित किया है।

आकाशदीप के 5 विकेट पर भारी पड़े ब्लंडेल के 89 रन, दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड मजबूत

क्राइस्टचर्च। टॉम ब्लंडेल की 89 रनों की शानदार पारी और गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आकाशदीप के पांच विकेट लेने के बावजूद न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम दिन का खेल समाप्त होने तक 116 रन पर छह विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है। मेजबान टीम की ओर से काइल जैमीसन और जैकब डफी ने दो-दो विकेट लिए।

भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले बोल्ड कर दिया। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने जैमीसन की छोटी गेंद पर छक्का लगाया, जबकि केएल राहुल ने शानदार ऑन ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। पडिक्कल ने हेनरी की गेंद पर स्क्वायर ड्राइव से एक और चौका लगाया लेकिन जैमीसन की गेंद पर ड्राइव खेलने के प्रयास में विकेटकीपर को कैच दे बैठे। वह 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल और शुभमन गिल ने पारी को संभालने की कोशिश की। हेनरी के ओवर में न्यूजीलैंड ने राहुल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील पर रिव्यू भी लिया लेकिन भारतीय बल्लेबाज बच गए। हालांकि, चाय से ठीक पहले जैमीसन की शानदार गेंद गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के पास चली गई। गिल के आउट होने से भारत का स्कोर तीन विकेट पर 59 रन हो गया। चाय के बाद राहुल का साथ देने ऋषभ पंत आए। दोनों ने



संभलकर बल्लेबाजी की और चौथे विकेट के लिए साझेदारी बनाने की कोशिश की। पंत ने शुरुआत में आक्रामक रुख दिखाया लेकिन जैमीसन की गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में चूक गए। दूसरी ओर, राहुल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को थकाने की रणनीति अपनाई और लगातार 25 गेंदें बिना रन बनाए खेलीं। पंत ने भी शुरुआती तेजी के बाद धैर्य दिखाया और अपनी पहली 25 गेंदों पर नौ रन बनाए। इसके बाद पंत ने जैकब डफी की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा। उन्होंने नाथन स्मिथ की गेंद को स्लिप और गली के बीच से निकाल कर चौका भी लगाया। हालांकि, डफी के खिलाफ दोबारा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह चूक गए। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में चली गई, जहां जैमीसन ने शानदार कैच लपका। पंत 39 गेंदों पर 23 रन बनाकर लौटे। चार विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी राहुल पर थी। वह धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन डफी की गेंद पर स्क्वायर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्ररक्षक के हाथों में चली गई। राहुल 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने संभलकर बल्लेबाजी की। दोनों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी का सामना करते हुए विकेट बचाए रखे। इस दौरान जुरेल को जीवनदान भी मिला, जब जैमीसन की गेंद पर हेनरी निकोल्स उनका नीचा कैच नहीं पकड़ सके। दोनों बल्लेबाजों ने 15 से अधिक ओवर तक क्रीज पर टिककर भारत को संभालने की कोशिश की लेकिन दिन की आखिरी गेंद पर नाथन स्मिथ ने सुंदर को दूसरी स्लिप में कैच करा दिया। सुंदर ने 60 गेंदों पर 10 रन बनाए।

खेलो हिमाचल के तहत 15 दिसंबर से धर्मशाला में होंगी उपमण्डल स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं

धर्मशाला,एजेंसी। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने तथा उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के उद्देश्य से खेलो हिमाचल अभियान के तहत 15 दिसंबर से धर्मशाला में उपमण्डल स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन को लेकर शनिवार को एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

एसडीएम मोहित रत्न ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेलो हिमाचल अभियान के माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के साथ-साथ चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करने और स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबाल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, रस्साकशी तथा बास्केटबॉल सहित कुल 10 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://द्यद्धद्गद्यश-



द्धद्धद्गड्डष्द्धड्डद्य.द्धश्च.द्दश1.द्वठ्ठ/ अथवा क्यूआर कोड स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुल 608 टीमों ने पंजीकरण करवा चुकी हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

एसडीएम ने बताया कि प्रतियोगिताओं के विभिन्न चरणों में विजेता प्रतिभागियों एवं टीमों को आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपमण्डल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 41 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को दो लाख रुपये, द्वितीय विजेता को डेढ़ लाख रुपये तथा तृतीय विजेता को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 31 लाख रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 15 लाख रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी।

नाइजीरिया की मारिया वोफिल को मिला 'वुमन ऑफ द ईयर' पुरस्कार

नई दिल्ली। नाइजीरिया की मारिया वोफिल को 2026 का विश्व एथलेटिक्स 'वुमन ऑफ द ईयर' पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें एथलेटिक्स में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अवसर तैयार करने के प्रति लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। विश्व एथलेटिक्स ने शनिवार को उक्त जानकारी दी। खेल प्रशासन के क्षेत्र में अनुभवी वोफिल ने कई दशकों से खेल नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया है। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों की खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा महिला खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रशासकों की नई पीढ़ी तैयार करने से जुड़ी पहलों का समर्थन किया है।

वोफिल 2005 से 2013 तक नाइजीरिया एथलेटिक्स महासंघ की महासचिव रही हैं। उन्होंने नाइजीरिया के संघीय युवा एवं खेल विकास मंत्रालय में भी वरिष्ठ पदों पर काम किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों में कई नेतृत्वकारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने नाइजीरिया के खेल महासंघों के संचालन मंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पुरजोर पैरवी की। उनके प्रयासों से देश के राष्ट्रीय खेल महासंघों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त स्थानों को मंजूरी देने की पहल को समर्थन मिला। अफ्रीकी महाद्वीप के स्तर पर भी वोफिल ने 2024 में अफ्रीकी एथलेटिक्स परिसंघ की लैंगिक नेतृत्व कार्यबल के गठन की पहल की। उन्होंने पूरे अफ्रीका में लैंगिक नेतृत्व से जुड़े सेमिनारों के आयोजन में भी सहयोग किया। महिला प्रशिक्षकों और खेल प्रशासकों को मार्गदर्शन देने के साथ उन्होंने महिला खेल नेतृत्व अकादमी (विश) कार्यक्रम के तहत भी योगदान दिया है। जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों में अबुजा संघीय राजधानी क्षेत्र में लड़कियों के लिए स्प्रिंट और रिले प्रतियोगिता शुरू करना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य जूनियर और सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार मिलने पर वोफिल ने कहा, 'यह वर्ष मेरे लिए वास्तव में विनम्रता का अनुभव कराने वाला रहा है और मैंने जो काम किया है, उसके लिए सम्मानित किए जाने पर मुझे बहुत गर्व है। मैं विश्व एथलेटिक्स के नेतृत्व के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने खेल की ईमानदारी और उसके विकास के प्रति निरंतर समर्पण पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं अफ्रीकी एथलेटिक्स परिसंघ, नाइजीरियाई ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल आयोग, नाइजीरिया एथलेटिक्स महासंघ और नाइजीरिया की पूर्व महिला खिलाड़ियों के संघ के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। वोफिल ने कहा, 'इस पुरस्कार ने मुझे एथलेटिक्स में अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी क्षमता से निभाते रहने के लिए नई ऊर्जा दी है। इसमें विशेष रूप से लैंगिक नेतृत्व, युवा खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल में मार्गदर्शन देने पर मेरा ध्यान रहेगा।'

एक नजर

इजराइल में राजनीतिक एकजुटता की पहल, नेतन्याहू आइजेनकोट को पहले पीएम बनाने को तैयार

तेल अवीव। इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के साथ एकता सरकार बनाने की पेशकश की है। नेतन्याहू ने कहा है कि यदि दोनों पक्षों के बीच एकता सरकार के गठन पर सहमति बनती है तो वह आइजेनकोट को पहले प्रधानमंत्री का पद संभालने देने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि इजराइल के सभी जायोनी दलों को एकजुट होकर देश के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही तात्कालिक चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने आइजेनकोट की पार्टी के साथ एकता सरकार बनाने के लिए वास्तविक, गंभीर और तेज गति से बातचीत शुरू करने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता सरकार ही इजराइल की सुरक्षा और भविष्य सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता है। नेतन्याहू के इस बयान को देश में राजनीतिक एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रस्ताव के तहत आइजेनकोट को पहले प्रधानमंत्री पद संभालने का अवसर देने की बात कही गई है। हालांकि, एकता सरकार के गठन और सत्ता साझा करने की व्यवस्था को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत तथा औपचारिक सहमति होना अभी बाकी है।

ईरान के अशांत सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या

तेहरान। ईरान के दक्षिण-पूर्वी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक सुन्नी धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, मृतक की पहचान बशीर सलाहजेही के रूप में हुई है। वह सरबाज काउंटी के प्रतिष्ठित सुन्नी धर्मगुरु थे। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि सलाहजेही की हत्या कुछ घंटे पहले एक कथित आतंकवादी हमले में की गई। एजेंसी ने इस वारदात के लिए अमेरिका और इजरायल के कथित समर्थित तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, अभी किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सिस्तान-बलूचिस्तान ईरान के सबसे गरीब प्रांतों में शामिल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटे इस इलाके में लंबे समय से सुरक्षा बलों और सशस्त्र संगठनों के बीच संघर्ष होता रहा है। इनमें अलगाववादी गुट भी शामिल हैं। हाल के दिनों में क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं में फिर तेजी आई है। इस प्रांत में बड़ी संख्या में बलूच समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें अधिकांश सुन्नी मुस्लिम हैं। इसके विपरीत ईरान की बहुसंख्यक आबादी शिया मुस्लिम है। धार्मिक और जातीय पहचान के साथ-साथ आर्थिक पिछड़ापन तथा अलगाववादी गतिविधियां इस क्षेत्र में लंबे समय से तनाव की वजह रही हैं।

अल्बानिया में सरकार विरोधी छात्र प्रदर्शन हिंसक, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग



तिराना। अल्बानिया में सरकार विरोधी आंदोलन ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया। राजधानी तिराना में प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग को लेकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जुटे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने दंगा नियंत्रण पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके। जवाब में पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। सरकार में कथित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोजगार के सीमित अवसर और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर लोगों में नाराजगी है। अक्टूबर के मध्य में तिराना से शुरू हुआ यह आंदोलन अब देश के अन्य शहरों तक फैल चुका है। इससे पहले भी कई प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और बैंकों में आगजनी की, दुकानों के शीशे तोड़े और सड़क से उखाड़े गए पत्थरों से पुलिस पर हमले किए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, शनिवार को कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत पर पत्थरबाजी की और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल 45 वर्षीय इंजीनियर एराल्दा बाजे ने कहा कि भ्रष्टाचार, गरीबी और पलायन की समस्या अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी उठाई। एक बैनर पर लिखा था, 'अल्बानिया बिकाऊ नहीं है। प्रधानमंत्री रामा की सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार करते हुए प्रदर्शनकारियों से बातचीत की अपील की है। आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार ने सस्ता ईंधन और गरीब परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने जैसे कदम उठाए हैं।

यमन के तट के पास हथियारबंद लुटेरों ने यूएई के मालवाहक जहाज को किया अगवा

सना। यमन के तट के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से जुड़े एक मालवाहक जहाज का सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, लुटेरे मछुआरों के भेष में यमन पहुंचे थे और वहां सोमालियाई समुदाय के बीच छिपकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूकेएमटीओ ने भी जहाज पर सशस्त्र हमलावरों के सवार होने की पुष्टि की है। यूकेएमटीओ के मुताबिक, यमन के बलहाफ बंदरगाह से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में एक मालवाहक जहाज पर हमलावरों ने कब्जा कर लिया। सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र के तीन सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अपहृत जहाज एमवी मार्सा विर्गो है। यह जहाज यूएई स्थित मार्सा ओशन शिपिंग कंपनी का है और पनामा के ध्वज के तहत संचालित हो रहा था। अधिकारियों के अनुसार, छह सोमालियाई हथियारबंद लुटेरे मछली पकड़ने वाली नाव से पुंटलैंड से रवाना हुए और अदन की खाड़ी पार कर यमन पहुंचे। सोमालियाई समुदाय के सूत्रों के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि लुटेरों ने मछुआरों का भेष धारण कर अपनी पहचान छिपाई थी। जहाज पर चालक दल के 19 सदस्य सवार थे। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, सभी सदस्य जहाज के सुरक्षित कक्ष में बंद हो गए हैं। हालांकि, उनकी मौजूदा स्थिति और अपहरणकर्ताओं की आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

कराची में छह मंजिला इमारत ढही, 9 की मौत और 11 लापता, 4 आरोपित गिरफ्तार



कराची,एजेंसी। पाकिस्तान के कराची में निर्माणाधीन छह मंजिला इमारत गिरने के हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। शनिवार सुबह बचावकर्मियों ने मलबे से एक और शव बरामद किया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय मुहम्मद अली के रूप में हुई है। हादसे के बाद से राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी भी 11 लोग लापता हैं, जबकि 14 लोग घायल हुए थे।

पाकिस्तान की उर्दू टेलीविज़न चैनल दुनिया न्यूज तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिओ न्यूज के मुताबिक, यह हादसा शुक्रवार को कराची की एडमिन सोसाइटी में बलूच कॉलोनी के पास हुआ था। निर्माणाधीन छह मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। घटना के तुरंत बाद 'रेस्क्यू 1122' सहित आपातकालीन बचाव दलों ने राहत अभियान शुरू किया। बचावकर्मियों ने हादसे के करीब दो दिन बाद एक मार्बल कारीगर को मलबे से जिंदा बाहर निकाला था। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल 14 लोगों में से 13 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बचाव दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मलबे के नीचे फंसे लोगों तक पहुंचना है। अधिकारी भारी मशीनों के इस्तेमाल से बच रहे हैं और हाथों से मलबा हटाने के साथ कंक्रीट के स्लैब को सावधानीपूर्वक काट रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारी मशीनों के इस्तेमाल से बचा हुआ ढांचा और अस्थिर हो सकता है। साथ ही मलबे में फंसे लोगों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मलबे के बीच रास्ते बनाए हैं, ताकि उन हिस्सों तक पहुंचा जा सके जहां लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी लापता लोगों का पता चलने तक अभियान जारी रहेगा। हादसे के बाद पुलिस ने इमारत गिरने के मामले में हत्या, लापरवाही और असावधानी समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, मामले में 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद सिंध सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मुराद अली शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में घटना की समीक्षा की गई। बैठक के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी (एसबीसीए) के महानिदेशक वसीम शमशाद को पद से हटाने का आदेश दिया गया। उन्हें स्थानीय सरकार सचिव के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह बिलाल मेमन को स्थानीय सरकार सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि आबिद सलीम को एसबीसीए का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा, कथित लापरवाही के आरोप में पूर्वी जिले के उपायुक्त नसरुल्ला अब्बासी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जुबैर शेख और एसबीसीए के अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने एसबीसीए के 16 संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले फरवरी में गैस विस्फोट के कारण कराची में एक इमारत ढह गई थी, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, पिछले साल जुलाई में लियारी इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने से 27 लोगों की जान चली गई थी।

बलूचिस्तान में चार पूर्व सैन्यकर्मी समेत 6 की हत्या – बीएलए ने ली जिम्मेदारी

क्वेटा। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने चगाई जिले में एक खनन परियोजना से अगवा किए गए छह लोगों की हत्या कर दी है। संगठन के मुताबिक, मारे गए लोगों में पाकिस्तान सेना और रेंजर्स के चार पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक इन हत्याओं और शवों की बरामदगी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

बलूचिस्तान की ऑनलाइन समाचार नेटवर्क 'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने बीएलए प्रवक्ता जियांद बलूच के हवाले से बताया कि संगठन के लड़ाकों ने 18 नवंबर को डलबंदिन के खरगोशकान इलाके में एक खनन स्थल पर कब्जा किया था। इस दौरान वहां मौजूद मशीनरी, वाहनों और उपकरणों को आग के हवाले कर दिया गया था। संगठन ने दावा किया कि खनन कंपनी के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 11 लोगों को अगवा किया गया था। इनमें से छह लोगों को मौत की सजा सुनाने के बाद मार दिया गया, जबकि पांच अन्य अब भी संगठन की हिरासत में हैं। बीएलए के अनुसार, यह कार्रवाई उसके कथित 'बलूच नेशनल कोर्ट' के फैसले के बाद की गई। बीएलए ने बताया कि मारे गए छह लोग अस्करी गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से खनन स्थल पर हथियारबंद सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। संगठन ने चार पूर्व सैन्य और रेंजर्स कर्मियों की पहचान भी बताई है। इनमें पंजाब के मियांवाली के सवाब जान, पेशावर के दरयाई के साहिल मुहम्मद, बलूचिस्तान के उस्ता मुहम्मद के मुबारक खान और सिंध रेंजर्स के पूर्व सदस्य अब्दुल मरजान शामिल हैं। संगठन का आरोप है कि पूछताछ और सबूतों की जांच के बाद इन लोगों के पाकिस्तानी सेना से संबंध होने की जानकारी मिली थी। बीएलए ने दावा किया कि निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले ये लोग वास्तव में सैन्य गतिविधियों का हिस्सा थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने खनन स्थल पर हुए हमले की पुष्टि की है, लेकिन अगवा किए गए लोगों को पूर्व सैन्यकर्मी बताए जाने के दावे पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों की ओर से छह लोगों की हत्या या उनके शव मिलने को लेकर भी अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच बीएलए ने बलूचिस्तान के अलग-अलग इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है।

अफगानिस्तान : स्कूल के पास भीषण धमाके में 6 छात्रों की मौत, 97 घायल



काबुल। अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत में शनिवार सुबह एक स्कूल के पास हुए जोरदार धमाके में छह छात्रों की मौत हो गई, जबकि 97 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों और घायलों की संख्या शुरुआती है और जांच के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। अंतराष्ट्रीय मीडिया अल जजीरा के अनुसार, कुनार प्रांतीय अस्पताल के प्रमुख मौला दाद ने बताया कि धमाके में 6 छात्रों की मौत हुई है और 97 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है और फिलहाल ये शुरुआती आंकड़े हैं।

कुनार के सूचना एवं संस्कृति विभाग के निदेशक मौलवी समी-उल-हक के अनुसार, धमाका शनिवार सुबह करीब 10 बजे पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सेर इलाके में एक मिडिल स्कूल के पास स्थित घर में हुआ। अधिकारियों के मुताबिक, जिस घर में विस्फोट हुआ, उसका इस्तेमाल खनन कार्य से जुड़े लोग कर रहे थे। बताया गया है कि वहां खनन में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक जमा करके रखा गया था। हालांकि, विस्फोट की सटीक वजह और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन ने भी घटना में हुए कुल नुकसान के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।

पाकिस्तान की सीमा से लगे कुनार प्रांत में जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। अधिकारी विस्फोट के कारणों और हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना के बारे में और जानकारी सामने आ सकती है। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में राजधानी काबुल के एक स्कूल परिसर में हैंड ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 9 से 14 साल की उम्र के 40 से अधिक बच्चे घायल हो गए थे।

लीबिया में सैन्य कार्रवाई को लेकर जेलेंस्की ने मेलोनी से मांगी माफी, बिना बताए चलाया था सैन्य ऑपरेशन



मॉस्को,एजेंसी। लीबिया के बेनगाजी बंदरगाह पर यूक्रेनी सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा कूटनीतिक विवाद सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कथित तौर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से इस ऑपरेशन को लेकर माफी मांगी है। इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन ने लीबिया में सैन्य कार्रवाई से पहले इटली को कोई सूचना नहीं दी थी। इस घटना ने यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार ने बेनगाजी में यूक्रेनी हमलों के संबंध में संसद या मीडिया से कोई जानकारी नहीं छिपाई है। उन्होंने लिखा, 'जेलेंस्की की माफी ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।'

वहीं, इतालवी अखबार 'फोग्लियो' ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि जेलेंस्की ने मेलोनी से इसलिए माफी मांगी, क्योंकि यूक्रेन ने लीबिया में किए गए सैन्य ऑपरेशन के बारे में रोम को पहले से जानकारी नहीं दी थी। इतालवी प्रधानमंत्री कार्यालय 'चिगी पैलेस' के अनुसार, शुक्रवार को जियोर्जिया मेलोनी और जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान मेलोनी ने बेनगाजी बंदरगाह पर यूक्रेनी बलों की कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता जताई। जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि यह सैन्य ऑपरेशन सहयोगी देशों के साथ पूर्व समन्वय के बिना किया गया था। उन्होंने मेलोनी को भरोसा दिलाया कि वह इटली की चिंताओं को समझते हैं। इतालवी सरकार के अनुसार, बेनगाजी बंदरगाह पर यूक्रेनी कार्रवाई ने लीबिया की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। साथ ही इससे रूस-यूक्रेन संघर्ष के भूमध्य सागर तक फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। इससे पहले शुक्रवार को एंटोनियो तजानी ने जेलेंस्की के उस दावे को गलत बताया था, जिसमें कहा गया था कि लीबिया में किया गया हमला अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ समन्वय करके किया गया था। इटली के उपप्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री माटेओ साल्विनी ने भी बुधवार को चिंता जताई थी कि लीबिया के बंदरगाह पर ड्रोन हमलों से भूमध्य सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

इस मामले में लीबिया की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोमवार को लीबियाई राष्ट्रपति परिषद के सदस्य मोसा अल-कोनी ने बेनगाजी बंदरगाह पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया और इसे अस्वीकार्य बताया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में लीबियाई नेशनल आर्मी की नौसेना के दो जवानों की मौत हुई थी। घटना के बाद लीबिया के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा था। बेनगाजी बंदरगाह पर कथित यूक्रेनी हमले और उसके बाद सामने आए कूटनीतिक विवाद ने भूमध्यसागरीय क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इटली की चिंता है कि बिना सहयोगी देशों को जानकारी दिए इस तरह के सैन्य अभियान चलाने से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। वहीं, लीबिया ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है।

बांग्लादेश में सियासी घमासान : अवामी लीग के खिलाफ बीएनपी, जमात और एनसीपी करेगी रैली

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अवामी लीग (एएल) के खिलाफ सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने दिसंबर में देशभर में रैलियां, जुलूस और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। ये कार्यक्रम ऐसे समय में होने जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग के खिलाफ राष्ट्रीय एकता बनाने की अपील की है। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी की अटकलों ने भी राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।

बांग्लादेश के अंग्रेज़ी दैनिक समाचार पत्र 'द डेली स्टार' के मुताबिक हाल के दिनों में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हिंसा और तोड़फोड़ के आरोपों के बाद देश में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने दिसंबर को 'विजय का महीना' बताते हुए अपने कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है।

गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद के मुताबिक बीएनपी के कार्यक्रम एक से 31 दिसंबर तक चलेंगे। वहीं, जमात-ए-इस्लामी ने 40 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा की है। एनसीपी भी देश के 64 जिलों और 13 महानगरों में रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। इस बीच अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस मुद्दे पर



प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बातचीत शुरू की है। बीएनपी अपने विजय माह कार्यक्रमों की शुरुआत एक दिसंबर को राजधानी ढाका के सुहरावर्दी उद्यान में एक विशाल रैली के साथ करेगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तारिक रहमान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा और इसमें सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। पार्टी के कार्यवाहक महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने नयापलटन स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।

बीएनपी सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी दिसंबर के लगभग हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। ज्यादातर आयोजन सभागारों के बजाय सड़कों और खुले मैदानों में होंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जाएगा कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ और गैरकानूनी जमावड़े का विरोध किया जाएगा। जमात-ए-इस्लामी ने 19 नवंबर को अपने 40 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत 21 नवंबर को बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद के उत्तरी द्वार पर रैली और जुलूस के साथ हुई। इसके बाद 25 नवंबर को 11 अन्य महानगरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जमात के महासचिव मिया गुलाम पोरवार ने कहा कि पार्टी जनता के साथ मिलकर फासीवाद का विरोध करेगी। फासीवाद के खिलाफ आंदोलन का मतलब वाहनों में आग लगाना या लोगों की हत्या करना नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आंदोलन के जरिए विरोध दर्ज कराना है। पार्टी के सहायक महासचिव हामिदुर रहमान आजाद के मुताबिक 31 दिसंबर तक रैलियां, जुलूस, चर्चा बैठकें और सामाजिक गतिविधियां जारी रहेंगी। जमात ने 13 दिसंबर को व्यापार सम्मेलन, 14 दिसंबर को शहीद बुद्धिजीवी दिवस, 15 दिसंबर को चर्चा कार्यक्रम और 16 दिसंबर को देशभर में विजय दिवस के जुलूस आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा 19 से 23 दिसंबर तक इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या की बरसी के अवसर पर बैठकें और प्रार्थना सभाएं होंगी। महीने के अंतिम पांच दिनों में रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर और जरूरतमंद स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनसीपी ने भी 23 नवंबर से अपना 39 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा।

रूस का दावा : रातभर में यूक्रेन के 1,246 ड्रोन मार गिराए, हथियार ले जा रहे 4 रेलवे इंजन भी निशाने पर



मॉस्को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में हवाई हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रातभर चले अभियान के दौरान देश के विभिन्न इलाकों में यूक्रेन के 1,246 ड्रोन को नष्ट कर दिया। इसके अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन के तीन क्षेत्रों में हथियार और सैन्य उपकरण ले जा रहे चार रेलवे इंजनों को भी निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि बीती रात वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के 1,246 फिक्स्ड-विंग मानवरहित हवाई वाहनों (ड्रोन) को रोककर नष्ट किया। ये ड्रोन ब्रियांस्क, बेलगोरोद, कुर्स्क, ओरियोल, स्मोलेंस्क, वोरोनिश, कलुगा, तुला, रोस्तोव, वोल्गोग्राद, सारातोव और समारा क्षेत्रों के ऊपर मार गिराए गए। इसके अलावा क्रास्नोडार क्षेत्र, मॉस्को क्षेत्र, क्रीमिया और बशकिरिया में भी ड्रोन नष्ट किए जाने का दावा किया गया है।

इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक अन्य बयान में बताया कि उसकी सेना ने रातभर की कार्रवाई के दौरान यूक्रेन के चार रेलवे इंजनों को निशाना बनाया। मंत्रालय के मुताबिक, इन इंजनों का इस्तेमाल हथियारों और सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए किया जा रहा था। रूसी सेना ने निप्रॉपेट्रोव्स्क क्षेत्र के सिनेलनिकोवो, झितोमिर क्षेत्र के कोरोस्तेन और खार्कोव क्षेत्र के ल्युबोटिन में ये हमले किए। रूस का दावा है कि इन स्थानों पर सैन्य सामान की आवाजाही में इस्तेमाल होने वाले चार रेलवे इंजनों को निशाना बनाया गया।

एक नजर

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं हर माह सात से पहले मिलेगा वेतन

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। श्रुति चौधरी शनिवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही थी। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय लाभों और पदोन्नति से संबंधित मांगों एवं समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवरेज के संबंध में मंत्री ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) को निर्देश दिए कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत उपलब्ध लाभों की जानकारी दी जाए। आशा वर्कर्स और ग्राम चौकीदारों की तर्ज पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) योजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इस प्रस्ताव को उचित स्तर पर विचारार्थ भेजा जाएगा। सहायिकाओं की पदोन्नति और इसके परिणामस्वरूप खाली होने वाले पदों को भरने के संबंध में मंत्री ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं, सुपरवाइजरों की भर्ती में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा देने की यूनियन की मांग पर भी चर्चा हुई। मानदेय के समय पर भुगतान को लेकर मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मासिक मानदेय प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले उनके खातों में जमा हो जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी भुगतान प्रक्रिया को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। मानदेय में वृद्धि की यूनियन की मांग पर भी विचार-विमर्श किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों के घर नियमित दौरा करने तथा पोषण ट्रैकर पर निर्धारित गतिविधियों का विवरण समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। टेक होम राशन (टीएचआर) और गर्म पका हुआ भोजन (एचसीएम) सेवाओं की सटीक एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ रिकॉर्ड 1.09 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का मुनाफा अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इनकी लाभप्रदता चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 17 फीसदी बढ़ी है। इसके साथ ही इनका कुल शुद्ध लाभ बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये (1.09 लाख करोड़ रुपये) से अधिक हो गया है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने शनिवार को एक्स पोस्ट में ये जानकारी दी। डीएफएस ने लिखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार सालाना आधार पर 15.5 फीसदी की वृद्धि के साथ 300 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। डीएफएस ने कहा, ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में अपना मजबूत वित्तीय प्रदर्शन जारी रखा। पीएसबी की लाभप्रदता अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16.9 फीसदी बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की फंसी हुई परिसंपत्तियां ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई हैं। इस साल 30 सितंबर 2026 तक इनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर 1.69 फीसदी और शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 फीसदी रह गया। डीएफएस ने कहा, ''प्रणालीगत सुधार, बेहतर संचालन व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता लाभप्रदता, कारोबार वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजीगत स्थिति में पीएसबी के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रही है।'' वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत बना रहा।



परिसीमन बिल लोकतंत्र और एससी-एसटी के हितों के लिए बड़ा खतरा : खरगे

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की मोदी सरकार पर परिसीमन विधेयक के जरिए देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने और सत्ता पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक लोकतंत्र तथा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकारों के लिए बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेना और देश में तानाशाही व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। शनिवार को संसद के आगामी सत्र की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद गठबंधन के नेताओं के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में खरगे ने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस संविधान संशोधन विधेयक का संसद में एकजुट होकर और पूरी मजबूती के साथ विरोध करेगा। खरगे ने कहा कि यदि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाती है, तो इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है और यदि पूरी सत्ता उसके हाथों में चली गई, तो वह अपने बहुमत का इस्तेमाल संविधान में अपनी इच्छानुसार बदलाव करने के लिए कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का एकजुट रहना जरूरी है।

एससी-एसटी के आरक्षण पर उठाए सवाल,

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठाए। संविधान के अनुच्छेद 330 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एससी-एसटी समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में



लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में इस संबंध में पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब 2026 की जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं, तो सरकार नई जनगणना का इंतजार क्यों नहीं कर रही? खरगे के मुताबिक, ताजा जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से एससी-एसटी समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन वर्गों को उनका उचित राजनीतिक अधिकार नहीं देना चाहती।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उठाए सवाल

खरगे ने परिसीमन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपे जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर मतदाता सूची से करोड़ों लोगों के नाम हटाए जाने और वोट चोरी जैसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उसी संस्था को देशभर में परिसीमन की जिम्मेदारी देना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो उसकी देखरेख में होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पर संदेह होना स्वाभाविक है। खरगे ने कहा कि परिसीमन के दौरान यह तय किया जाएगा कि कौन-सा निर्वाचन क्षेत्र सामान्य रहेगा, कौन-सा आरक्षित होगा और महिलाओं के लिए किन सीटों को आरक्षित किया जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों में चुनाव आयोग की भूमिका होगी। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है।

असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का दिया उदाहरण

कांग्रेस अध्यक्ष ने असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सामान्य तथा आरक्षित सीटों के स्वरूप में बदलाव के जरिए भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आशंका है कि इसी तरह की प्रक्रिया पूरे देश में अपनाकर भाजपा अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहती है।

400 पार के नारे की विफलता के बाद नई रणनीति का आरोप

खरगे ने 2024 के लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन देश की जनता ने उसे सफल नहीं होने दिया। अब लोकसभा की सीटों की संख्या 850 करने की योजना के जरिए भाजपा लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का रास्ता तैयार करना चाहती है। उन्होंने पिछली बार परिसीमन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद राजनीतिक दलों को तोड़ने और संख्या बल जुटाने की कोशिशों का भी आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने चीन की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश में भी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, जहां सभी लोग एकसाथ सरकार के समर्थन में खड़े दिखाई दें और लोकतांत्रिक असहमति के लिए कोई जगह न बचे। खरगे ने चेतावनी दी कि यदि भाजपा को मनमाने तरीके से सत्ता का विस्तार करने का अवसर मिला, तो देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस देश को मनुस्मृति की विचारधारा के अनुसार चलाना चाहते हैं। अंत में कांग्रेस अध्यक्ष ने दोहराया कि 'इंडिया' गठबंधन संसद के आगामी सत्र में प्रस्तावित संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक का संगठित तरीके से विरोध करेगा। विपक्ष का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी राज्यों, सामाजिक वर्गों और संवैधानिक संस्थाओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कार्यकर्ता 'जन-मन का मैनिफेस्टो 2027' घर-घर पहुंचाए : अखिलेश यादव



लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के संभावित प्रत्याशियों, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से 'जन-मन का मैनिफेस्टो 2027' यानी पीडीए का प्रणपत्र आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़े सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए कि वे जनता को प्रणपत्र की घोषणाओं और उनसे मिलने वाले लाभों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दें।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शनिवार को पोस्ट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति का उपाय अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सरकार बनाना है। अब तक लोगों ने दूसरों की सरकार बनाई है, लेकिन इस बार अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे और हर संकट से मुक्ति पाएंगे। उन्होंने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से आह्वान किया कि वे महिलाओं के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हर साल 40 हजार रुपये देने, मोबाइल उपलब्ध कराने, पीडीए के उत्थान से जुड़ी योजनाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों के महत्व के बारे में बताएं। साथ ही युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार को लेकर पार्टी की ओर से किए गए वादों की जानकारी भी दें। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं को पीडीए के अर्थ को भी जनता के बीच स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने पीडीए को 'पीड़ित, दुखी और अपमानित' वर्गों से जोड़ते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न साइकिल का बटन दबाने की अपील करने को कहा। अखिलेश यादव ने पीडीए की एक नई व्याख्या भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए पीडीए का अर्थ 'पढ़ाई, दवाई और आमदनी' है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसी संदेश के साथ जनता के बीच पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क करना चाहिए।

आर्थिकी व आस्था के बीच अद्भुत समन्वय का बेहतरीन प्रयास है बनारस बिनाले: योगी

वाराणसी,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में सीआईआई बनारस बिनाले-2026 का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बनारस बिनाले आर्थिकी व आस्था के बीच अद्भुत समन्वय का बेहतरीन प्रयास है। उन्होंने आशा जताई कि काशी की तरह बनारस बिनाले भी जीवंतता का प्रमाण बनेगा। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि नीयत साफ, नीति स्पष्ट हो तो नियंता की कृपा भी बरसती है।

उन्होंने कहा कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था एक-दूसरे के पूरक हैं। आस्था और आर्थिकी के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक हैं। महाकुम्भ इसका उदाहरण है। विकास व विरासत के अद्भुत यात्रा का परिणाम है कि कभी बीमारू उत्तर प्रदेश को भारत के इकॉनमी के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। देश के अंदर सर्वाधिक दो लाख करोड़ रुपये यूपी में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि अविनाशी काशी भारत की संस्कृति, अध्यात्म, ज्ञान व संगीत की अद्भुत भवभूमि है। जो काशी में है, वही सर्वत्र दिखाई देगा। जो यहां नहीं है, वह अन्यत्र भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। मार्क ट्विन ने कहा था कि काशी इतिहास से भी पुरानी व परंपरा से भी प्राचीन है। काशी प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक विरासत की केंद्रबिंदु रही है। काशी की पौराणिकता का उल्लेख कर कहा कि अनेक कथाओं व पाणिनी की रचनाओं में काशी का उल्लेख मिलता है। दुनिया के पहले सर्जन सुश्रुत ने भगवान धन्वतंरि से काशी में शल्य चिकित्सा का



ज्ञान अर्जित किया था। यहां के विद्वानों ने सूर्य, चंद्र व ग्रहों का सटीक अनुमान लगाया था। काशी का पंचांग सबसे व्यावहारिक माना जाता है और लोग इसी के अनुरूप पर्व और मांगलिक कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काशी ने भारतीय साहित्य को भी कालजयी रचनाएं दी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने यहां रहकर रामचरित मानस की रचना की तो संत कबीर ने दोहे से समाज को नई दिशा दी। आधुनिक युग में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। यहां संतों की लंबी परंपरा रही है। जो भी काशी आया, यहीं का होकर रह गया। जिसने जिस दृष्टि से काशी को देखा, उसे वैसे ही सृष्टि जीवन में देखने को मिली। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने ज्ञान के लिए सारनाथ को उपदेश की पहली भूमि के रूप में चुना। यहां भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। बनारस बिनाले का कार्यक्रम काशी की अद्भुत परंपरा के साथ मेल खाता है। 1995 में वेनिस बिनाले से इसकी शुरुआत हुई और भारत में यह 2012 में प्रारंभ हुआ। अब यह वेनिस से कोच्चि और कोच्चि से काशी में पहुंच रहा है। काशी की विरासत उतना ही प्राचीन है, जितना दुनिया का इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की सांस्कृतिक परंपरा इसे जीवंत स्मारक के रूप में प्रस्तुत करती है। यहां घाट-गंगा की पावन धारा, वस्त्र-संगीत, ज्ञान की समृद्ध परंपरा भी है। यह केवल ट्रेडिशन तक मौजूद नहीं है, इसने आधुनिकता को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। परतंत्र भारत में 1916 में महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी में बनारसी रेशम, जरी के साथ ओडीओपी उत्पाद भी दिखेंगे। नए खरीदार के साथ ही काशी को नया सम्मान भी मिलता है। उन्होंने कहा कि बीएचयू का भारत कला भवन, ज्ञान प्रवाह, नागरी प्रचारिणी सभा, पेशवा हवेली, संग्रहालय, विश्वविद्यालय व उद्योग सांझी सांस्कृतिक यात्रा से जुड़े रहे हैं। काशी बिनाले का प्रथम संस्करण नई परंपरा की नींव रख रहा है। सदियों से ज्ञान की राजधानी काशी आधुनिक कला, संवाद की प्रमुख राजधानी के रूप में गिनी जाए। उक्त के साथ ही नमो घाट, प्रदर्शनियों, फिल्म, शिल्प व साहित्य के माध्यम से काशी की विरासत को नई दृष्टि मिल रही है।

काशी तमिल संगमम् 5.0 : नमो घाट पर सजी सांस्कृतिक संध्या, काशी और तमिलनाडु के कलाकारों ने बांधा समां

वाराणसी,एजेंसी। काशी तमिल संगमम् 5.0 के उद्घाटन दिवस पर शनिवार शाम वाराणसी के नमो घाट स्थित मुक्ताकाश प्रांगण में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में काशी और तमिलनाडु के कलाकारों ने भजन, संगीत, लोकनृत्य और नृत्य-नाटिका की मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विविध प्रस्तुतियों के माध्यम से दोनों क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और लोक परंपराओं का सुंदर संगम देखने को मिला। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंच कला संकाय से जुड़े विजय कपूर और उनके समूह की भजन प्रस्तुतियों से हुआ।

कलाकारों ने 'पूजा है, धरम दीन है, ईमान है गंगा' और 'जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया' जैसे भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद चेन्नई (तमिलनाडु) की गायिका यू. ई. सिंधुजा ने अपनी मधुर गायकी से श्रोताओं का मन मोह लिया। वहीं, संगीता तिरुपति और उनके समूह ने तमिलनाडु की पारंपरिक लोकनृत्य शैली 'कोलाट्टम' की आकर्षक प्रस्तुति दी। पारंपरिक वेशभूषा, लयबद्धता और लोकनृत्य की विशिष्ट शैली ने दर्शकों को



तमिल संस्कृति की जीवंत झलक दिखाई। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में अनन्या सिंह और उनके समूह ने शिव स्तुति एवं 'त्र्यम्बक नाद' पर आधारित नृत्य-नाटिका का मंचन किया। इस कलात्मक प्रस्तुति में शिव आराधना के माध्यम से उत्तर और दक्षिण भारत की साझा आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और एकात्मता के भाव को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया गया। सांस्कृतिक संध्या का समापन गणानप्रकाशम और उनके समूह की ऊर्जावान प्रस्तुति 'करुप्पसामी अट्टम' से हुआ। तमिलनाडु की इस पारंपरिक लोकनृत्य शैली के माध्यम से कलाकारों ने वहां की लोकसंस्कृति, परंपराओं और लोककलाओं की समृद्ध विविधता से दर्शकों को परिचित कराया। कार्यक्रम में एक के बाद एक प्रस्तुतियों ने काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों से विद्यमान सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंधों को नई अभिव्यक्ति दी। संगीत, भक्ति और लोककलाओं के इस अनूठे संगम ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत में निहित एकता का सशक्त संदेश दिया।

बिसलेरी ने पश्चिम बंगाल में कोलीफॉर्म मिलने के मामले में एफएसएसएआई से समीक्षा की मांग की

नई दिल्ली। बोतलबंद पेयजल विनिर्माता कंपनी बिसलेरी ने पानी की जांच को लेकर समीक्षा की मांग की हैं। बिसलेरी ने शनिवार को कहा कि दो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्वतंत्र जांच में पश्चिम बंगाल से लिए गए उसके पानी के नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। कंपनी ने जारी एक बयान में खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से प्रयोगशाला के निष्कर्षों में अंतर के कारणों की जांच करने का आग्रह किया है। बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का यह बयान एफएसएसएआई के उस ताजा आदेश के बाद आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल से लिए गए एक नमूने के प्रयोगशाला की जांच में विफल रहने के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।

दरअसल, जलपाईगुड़ी जिले के तेलीपाड़ा स्थित कंपनी की विनिर्माण इकाई से लिए गए एक नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित तेलीपाड़ा प्लांट के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बैच (PB201) में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलने के



मामले में बिसलेरी ने एफएसएसएआई से जांच रिपोर्टों की समीक्षा की मांग की है। एफएसएसएआई के ताजा आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बिसलेरी ने कहा है कि उसने नियामक के निर्देश पर अपने बोतलबंद पेयजल के उक्त बैच को पहले ही बाजार से वापस मंगा लिया था, जिस पर 12 अगस्त, 2026 को प्रतिबंध लगाया गया था।

कंपनी ने कहा कि उसी बैच के नमूनों की स्वतंत्र जांच में अलग परिणाम सामने आए हैं। कंपनी ने कहा, 'बिसलेरी ने अलग से एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला में उसी बैच के नमूनों की स्वतंत्र जांच कराई, जिसमें पाया गया कि नमूना कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के लिए लागू मानक और अन्य सभी लागू खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। इसके अलावा, एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त एक अन्य स्वतंत्र प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की रिपोर्ट में भी कहा गया कि नमूना कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के लिए लागू मानक के अनुरूप है। बिसलेरी ने कहा, 'नियामकीय और स्वतंत्र जांच के निष्कर्षों के बीच अंतर की गहन समीक्षा किए जाने की जरूरत है।' कंपनी ने एफएसएसएआई से नमूना लेने की प्रक्रिया, परीक्षण पद्धति, प्रयोगशाला निष्कर्षों और परिणामों में अंतर के लिए जिम्मेदार किसी भी कारक की जांच करने का आग्रह किया।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)